कि जैसे रोज़ाना हाऊस में बहुत कम लोग रहते हैं शाम को लेकिन आज कम से कम वैसा नहीं है। संख्या कुछ ज्यादा है और मैं समझता हूं कि वे न सिर्फ आडवाणी जी को सुनने के लिए यहां बैठे हैं, यात्रियों की सुरक्षा के बारे में जानने के लिए बैठे हैं, किसानों के बारे में भी थोड़ा सोच-विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि ये मसायल हमेशा आते रहते हैं लेकिन कुछ ठोस कदम उठाकर, कुछ साइंटिफिक एप्रोच से इनका हल निकालना चाहिए और भविष्य में किसान भाइयों को ऐसी आपदाओं का सामना करने की परिस्थिति न आए, इसके लिए हुकूमत जो कुछ कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को वह करना चाहिए। यह जो एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई गई है, उसको हमें देखना होगा क्योंकि लगता है कि वह उतनी सैटिरफैक्टरी नहीं होगी जैसा कि सुनने में आ रहा है और अखबारों में भी पढ़ने को मिल रहा है। मैं फिर कृषि मंत्री जी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले भी जैसा कहा गया कि वे नौजवान हैं, कृषि उत्पादन के क्षेत्र से आए हैं, इसलिए किसानों के लिए, उनकी भलाइ के लिए वे पूरी कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद।

उपसभापति : आप इतना इमोशनली बोले लेकिन कोई कम्पैरिज़न थोड़े ही होता है। अमरनाथ के यात्रियों के लिए भी हम दुख प्रकट करेंगे और किसानों के लिए भी दुख प्रकट करेंगे, दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं।

Now, if the House so agrees, we will ask the Home Minister to make the statement. Then, if the House so agrees, we will continue with it. Okay.

STATEMENT BY MINISTER

Incidence of killing by the Militants in Jammu and Kashmir on the intervening night of 1st and 2nd August, 2000

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Madam, a series of ghastly incidents perpetrated by militants, taking a toll of as many as 80 lives, have been reported from Jammu and Kashmir on the night of 1st and 2nd August, 2000.

In the first incident, at about 18-45 hours on 1st August, a group of terrorists fired indiscriminately at Pahalgam where Amarnath Yatris were camping. The incident took place across Lidder Nallah on the road leading to Aroo when terrorists fired at two Langars and CRPF personnel. The firing was retaliated by the CRPF. 27 persons, including two police personnel, have been killed and 50 injured. Two militants responsible for the firing were also killed on the spot. From them, the following recoveries have been effected: AK Rifles-2, AK Magazines- 19, Rifle grenades--8, Hand-grenades--2, Grenade launcher--1, Rounds--55, Transistor--1.

In the second and third incidents, the militants had attacked two brick kiln labour camps, one at Mir Bazar, Quazigund in Anantnag District, the other at Mir Nowgam (Achhabal). 19 labourers were killed at Mir Bazar and 7 labourers at Mir Nowgam. During the same night, in Pogal Paristan in Ramban area (Doda District), another group of militants killed 14 persons. In the same district in village Keyar, eight members of a village defence committee were killed by terrorists. The sixth incident took place at Kalaroos (Kupwara district) where five members of a Muslim family were massacred.

The State Government has initiated precautionary and relief measures. Special Secretary in the Department of J and K Affairs, along with DG, CRPF have been deputed to J and K to review the situation and the security arrangements along with the security forces in the field.

Consequent on the cease-fire declaration made by the Hizbul Muzahideen and the Government's positive response to this offer, there have been reports that some of the other militant outfits, with a large component of foreign mercenaries, who were unhappy about the offer of Hizbul Mujahideen, may create problems and escalate violence. The security forces had been alerted of this and have been asked to be more vigilant. It is because of this vigilance that the security forces had foiled an attempt of the militants to attack the Amarnath pilgrims in a Jammu camp on the morning of Ist August. In this clash, one militant was killed and another injured.

No words would be too strong to condemn these outrageous incidents of violence which are no doubt part of the continuing proxy war being waged against us by a hostile neighbour. But the Government feels that this latest outburst of violence is also a determined bid by those upset at the prospects of peace to abort the initiative taken by the Hizbul Mujahideen last week.

The Government is determined to continue the Amarnath Yatra with renewed security measures and to provide all necessary protection to the common people. Besides, the Government will persevere in its efforts to bring normalcy to the State of Jammu and Kashmir by engaging in a dialogue with the peace-loving people.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is a very condemnable act. Now, Dr. Manmohan Singh.

DR. MANMOHAN SINGH (Assam): Madam, we condemn the ghastly act of terrorism which have claimed the lives of 80 innocent people and several people have been injured. Our sympathies are with the members of the bereaved families, and those who have been injured, we wish them speedy recovery. Madam, there are certain issues which arise out of these incidents. The first issue is the adequacy of security arrangements that have been made to protect the yatries on pilgrimage to the sacred Amarnath Shrine. I would like the hon. Home Minister to tell the House whether the Government is fully satisfied that all necessary security arrangements are in place in this regard. Certainly, yesterday's tragic incident reveals that there are visible gaps in the security arrangements. We urge the Government to review these arrangements on a top priorty basis and plug the loopholes, if there are any, so that such incidents do not take place again. Madam, the second issue is, we must go behind this renewed outburst of terrorist activities in the way of the ceasefire offer of Hizbul Mujahideen. I would like the hon. Home Minister to tell us, if he can, as to what, in the Government's opinion, is the motivation behind these terrorist attacks. Is it to abort the peace process? Is it to fan a communal strife in our country, at large?

Madam, there are also reports that even within the Hizbul Mujahideen movement, there are differences with regard to the ceasefire offer. I would respectfully request the hon. Home Minister to enlighten the House, if it is possible to do so, on this occasion.

Madam, while we are in favour of all possible measures to restore peace and normalcy in Jammu and Kashmir and to promote a broad-based dialogue, involving all shades of public opinion, we will need to proceed cautiously, mindful of the various mine-fields on the road to peace.

The third question that I have to ask, Madam, is, what the Government's assessment is of Pakistan Government's attitude to the ceasefire offer of Hizbul Mujahideen. Do we have any evidence that Pakistan is excercising a restraining influence on the various militant groups, hitherto active in Jammu and Kashmir? If not, what strategy do we have in mind to ensure that the offer of Hizbul Mujahideen really paves the way for an endurable peace in Jammu and Kashmir?

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, गृह मंत्री का वक्तव्य बहुत-सी जानकारी देश को देने जा रहा है। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी देश को मिलेगी, ऐसी मुझे आशा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान बहुत कुछ हुआ और पिछले चौबीस घंटे में लगभग

90 हत्याएं हुईं, यह बताया गया है कि अररी से चौरासी के लगभग हत्याएं हुई जबकि स्टार न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया है कि 90 से अधिक व्यक्ति मारे गए हैं और सौ के लगभग घायल हुए हैं। यह सही है या गलत है अगर इसका स्पष्टीकरण हो जाए तो ठीक रहेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व किस पर था? सुरक्षा बल पर था? सेना पर था? या कश्मीर सरकार की पुलिस पर था? लगभग दो वर्ष पहले जब ऐसी घटनाएं हुई थीं, इस प्रकार की धमकियां दी गई थीं तो उनकी जांच हुई थी। यह आशा की गई थी, यह विश्वास दिलाया गया था कि अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व सेना को सौंप जाता रहेगा। क्या इस बार अमरनाथ यात्रियों की रक्षा के लिए सेना के हाथ में कुछ अधिकार दिए गए थे? अगर नहीं दिए गए थे तो उसके क्या कारण थे? उपसभापति जी, जहां तक जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा की बात है, गृह मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि वहां के मुख्य मंत्री भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। इसलिए निकले हुए हैं क्योंकि उन्हें अपने राजनैतिक कार्यों के लिए समर्थन जुटाना है। उन्हें सुरक्षा की चिंता नहीं है, लोक व्यवस्था की चिंता नहीं है। वे यह कह कर नहीं बच सकते कि यह भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। यह तो राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने इस उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभाया है? जहां तक गृह मंत्री जी ने कहा कि हमारे पड़ोसी द्वारा एक प्रॉक्सी वार छेड़ी गई है तो निश्चित रूप से यह प्रॉक्सी वार बहुत दिनों से चली आ रही है। उसके बाद भी यदि मुख्य मंत्री अपना नब्बे प्रतिशत समय अपने राज्य में न बिताकर राजानैतिक कार्यों में लगाएं, सुरक्षा की बात न करें तो क्या यह दुर्भाग्य की बात नहीं है? एक अन्य बात जो सामने आई है वह यह है कि गुप्तचर विभाग की सेवाएं बार बार कश्मीर के मामले में असफल क्यों हो रही हैं? मैं पिछले दिनों, उपसभापति जी, कश्मीर गया था। वहां पर एक दर्जन से भी अधिक गुप्तचर विभाग की संस्थाएं हैं। भारत सरकार की भी अनेक हैं, राज्य सरकार की भी अनेक है और कुछ स्थानीय भी हैं। लेकिन उनके बीच में तालमेल का घोर अभाव है। उनके बीच तालमेल का घोर अभाव है इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को अवश्य होगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में यहां गुप्तचर विभाग की असफलता सामने आई है? बार बार गुप्तचर विभाग या गुप्तचर विभाग से जुड़ी संस्थाएं निरन्तर असफल क्यों हो रही हैं, क्यों वह आतंकवाद को रोक नहीं पा रही है, कहां कठिनाई है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि भारत में यह जो आतंकवाद चारों ओर सक्रिय है, विशेषरूप से कश्मीर में इसका मुख्य कारण क्या है? हिजबुल मुजाहिदीन के साथ शांति वार्ता हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें धोखा देने की चेष्टा की जा रही हो, एक हमसे शांति की बात कर रहा हो और बाकी लश्करे तोहबा आदि इसकी आड़ लेकर और अधिक उपद्रव करने की सोच रहा हो? कहीं शांति की बात से हमारी जो सेना या सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं उनका मनोबल तो नहीं गिर रहा है? क्या उनसे ऐसा तो नहीं कह दिया गया है कि आप ढीले हो जाइए क्योंकि हमने भी कह दिया है कि इस अवधि में हम भी आतंकवाद के प्रति नरम हो जायेंगे? कम से कम हिजबुल मुजाहिदीन के साथ अब आतंकवाद का कोई तमगा तो लगा नहीं है तो फिर कैसे पता लगे कि कौन आंतकवादी किस दल का है? हिजबुल मुजाहदीन का कौन है और लश्करे तोहबा का कौन है? इससे क्या पुलिस के मन में या सुरक्षा बलों के मन में दुविधा की स्थिति उत्पन्न तो नहीं होगी यह मैं जानना चाहता हूं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह जो स्थिति है भविष्य में इसका समाधान कब निकलेगा? कम से कम तीर्थ यात्रिओं के संबंध में यह तो आपने आश्वस्त किया है कि तीर्थ यात्रा बराबर जारी रहेगी। लेकिन तीर्थ यात्रा के दौरान पर्याप्त सुरक्षा

तीर्थ यात्रियों को मिले इसका दायित्व किसे भविष्य में दिया जाएगा, यह कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें?

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, सबसे पहले मैं यह जो अफसोसनाक और दर्दनाक हमला आतंकवादियों की ओर से हुआ और जिस में इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इसके लिए मैं अपना गम और गुस्से का इजहार करता हूं। गृह मंत्री, लीडर आफ दि अपोजीशन और अपने बाकी तमाम कुलीग्स के साथ मैं अपने आपको अपनी पार्टी के साथियों को इस से संबद्ध करता हूं। जो स्टेटमेंट यहां आया है इसमें मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि पैरा 5 में है कि "Consequent on the cease-fire declaration made by the Hizbul Mujahideen and the Government's positive response to this offer, there have been reports that some of the other militant outfits with a large component of foreign mercenaries who were unhappy about the offer of Hizbul Mujahideen may creat problems and escalate violence."

इससे मैं और भी ज्यादा गुस्से का इजहार करता हूं। सरकार जब कोई पीस प्रोसेस स्टार्ट कर रही है तो यह अच्छी बात है। हिजबुल मुजाहिदीन ने सीज फायर डिक्लेयर किया और भी आर्गनाइजेशन, जो आउट फिट्स हैं उनके साथ पीसफुल माहौल में बातें शुरू हो.यह हम चाह रहे हैं, आप चाह रहे है और पूरा देश चाह रहा है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं। चाहे वह सीमा के पार पाकिस्तान में बैठे हों या सीमा के अंदर घुसपैठ करके बैठे हों। जो आपकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 180 लोग मारे गए और भी कितने लोग मारे गए होंगे पता नहीं। बहुत से इंजर्ड है। इससे ज्यादा कोई अफसोसनाक बात नहीं हो सकती है। जिस माहौल में यह हुआ और दो सप्ताह से जिस तरह से इसमें पूरी चौकसी दृष्टि चाहिए थी वह नहीं रही क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी साथ थी। हर साल अमरनाथ यात्रा में हजारों लोग जाते हैं और उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त बराबर होता है। मैं खुद 1996 में वहां गया था। वहां हर पहाड़ की चोटी पर, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पैरा मिलेटरी फोर्सेज और आर्मी तैनात थी। वहां कुदरती आफत आ गई, वह अलग बात है। लेकिन पूरा डिटरमिनेशन था। मिलिटेंसी 10-12 साल से वहां पर है लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि यात्रियों के ऊपर हमला कर दे। तो इस तरह का बंदोबस्त होता है। हर साल यह बंदोबस्त किया जाता है। आपके जमाने में भी किया गया और इस बार यह खबर मिलने के बावजूद भी कुछ पीस इनिशियेटिव वालू होने के बावजूद भी जब हम यह समझ रहे हैं कि सियासी तौर पर, टैक्टीकली भी उनकी तरफ से हमला हो सकता है तो हमने ढील बरती। यह रिपोर्ट में भी है कि जिस जगह पर हमला हुआ पहाड़ के उस पर से वह आए। पूरा रूट सेनेटाइज़ किया जाता है, कैंप के आसपास सेनेटाइज़ किया जाता है। जब मुख्य मंत्री जाते हैं, मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं और यहां तक कि जब सांसद कश्मीर में जाते हैं तो उस एरिया और पूरे रूट को सेनेटाइज़ किया जाता है। यह भी सेनेटाइज्ड रूट है, इनरूट कैम्प्स थे, फिर भी नाले के उस पार से वह चले आए। इस में ढील बरती गई। मेरा पहला सवाल है कि क्या सरकार हिजबुल के सीज फायर आफर के बाद आपके एक्सेप्टेंस के बाद नॉमीनेट करने के बाद कि यह मीडियेटर होंगे, इंटरलोप्यूटर होंगे, आप में कंप्लासेंसी हो गया, आप में संतोष हो गया? हमने इस सरकार में कई बार देखा है कि थोड़ा आधा कदम बढ़ाने के बाद भाषणबाजी बहुत कर देते हैं लेकिन जो बंदोबस्त होना चाहिये, जो चौकसी बरतनी चाहिये, उसमें ढील दे देते हैं। आप समझते हैं कि हमारी फतेह हो गई है और

जश्ने फतेह मनाने चले जाते हैं। यह इसलिए बहुत ज्यादा मंहगा साबित हो रहा है। पेरा नम्बर 6 के सेकेंड सेंटेनेंस में आप देखेंगे, " But the Government feels that this latest outburst of violence is also a determined bid by those upset at the prospects of peace." सही बात है। उनकी तरफ से डिटरमिन्ड अटेम्प्ट्स हो रहा है। हमारा डिटरमिनेशन कहां गया? हम पीस प्रोसेस को ज्योपार्डाइज़ नहीं करने देंगे जो भी थोड़े बहुत पोजिटिव इनिशियेटिव हुए हैं, उनको बरकरार रखेंगे, हमारे पास खबर है कि उनका डिटरमिनेशन था, हमारी तरफ से दुगुना, चौगुना डिटरमिनेशन होना चाहिये था कि हम किसी भी सेक्शन को चाहे सीमा के इस पार से हो या उस पार से हो, इसे हम तोड़ने नही देंगे। मंत्री महोदय बताएं, यह हमारा दूसरा सवाल है कि हमारा डिटरमिनेशन कहां गया? मैं उस सरकार के गृह मंत्री से यह पूछ रहा हूं जो कश्मीर के बारे में प्रोएक्टिव होंगे, इसके लिए देश की जनता के सामने वचनबद्ध हैं। मैं उस सरकार से पूछ रहा हूं जो यह कहती है कि हम प्रोएक्टिव पॉलिसी कश्मीर के लिए लाएंगे। मैं उस पोलिटिकल लीडर से पूछ रहा हूं जिन्होंने पिछले 10-15 साल से कश्मीर को मुद्दा नम्बर एक रखा है? उस जगह पर हम ऐसे मोड़ पर पहुंचे हैं जहां हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि वार्ता शुरू हो, बोली से समाधान निकले, गोली से नहीं। लेकिन जो लोग चाहते हैं गोली से कश्मीर का मामला आगे बढ़े उसको रोकने के लिए जो डिटरमिनेशन आपकी सरकार के पास होना चाहिये था, वह नहीं रहा। हमने सुना है इस सरकार से जिसने कहा जीरो टोलरेंस टू टेररिस्ट्स। वह ज़ीरो टारलेंस कहां गई? चौथा सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपने थ्री प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी की बात कही थी कश्मीर के बारे में। आपने यह कहा था कि अगर ऐसा हादसा होगा और बेगुनाह लोग मारे जाएंगे तो फिर गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ कर मैं क्या करूंगा। हम सिर्फ उन बातों को याद दिलाना चाह रहे हैं। नरेन्द्र मोहन जी ने भी यही कहा कि तालमेल होना चाहिये, अलग अलग एजेंसीज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट की हैं, पेरा मिलिटेरी फोर्स है, स्टेट पुलिस है, सेंट्रल फोर्सिज़ हैं। क्या एन.डी.ए. के अन्दर भी तालमेल है, जो सरकार चला रही है, जिससे हम बावस्ता हैं कि हमारी समस्या का समाधान होगा? पिछले एक महीने से हम एन.डी.ए. में कुश्ती देख रहे हैं, कश्मीर के मामले में, ऑटोनोमी के मामले पर। जब सब से ज्यादा कोशिश होनी चाहिये इकट्ठा हो कर एकत्रित हो कर आल पार्टीज़ मीटिंग बुला रहे हैं, सही बात है होनी चाहिये, हमें डिटरमिनेशन दिखाना चाहिये। यहां कोई पार्टी का अंतर नहीं है, सरकारी पक्ष और विरोध पक्ष नहीं है। कश्मीर का मामला हल होना चाहिये। हम सब इकट्ठे हैं इस जगह पर लेकिन एन0डी0ए0 के अन्दर जो कोहिरेंट पॉलिसी होनी चाहिये, वह नहीं है। पूरा देश देख रहा है। सरकार जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट के साथ तालमेल करेगी लेकिन आपके घटक कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री ने विश्वासघात किया है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिये। यह जो गलत मेसेज जा रहा है जो हमारा डिटरमिनेशन होना चाहिये उसमें वार्ता के ज़रिये समाधान करने में, उसमें कमी आ रही है ऐसा हमें लग रहा है। उसको दूर करने के लिए जो मेसेज आप देंगे पूरे विश्व के सामने देंगे, देश के अन्दर देंगे, देश के बाहर जो दुश्मन बैठे हैं उनको भी क्या मेसेज आप देना चाहे रहे हैं कि हम कितने डिटरमाइंड है, यह आप बताएं? मैडम मैंने पिछले सप्ताह ही अमरनाथ यात्रा के बारे में इसी सदन में मामला उठाया था। यह भी कहा था कि वहां टेंशन क्रीएट किया जा रहा है। जो परेशानी यात्रियों को थी, सरकार को उसके बारे में पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपने भी मैडम चेयर से बैठकर कहा था कि कुछ परमानेंट साल्यूशन होना चाहिए और सरकारी पक्ष से यह कहा गया था - मंत्री जी ने उस समय कहा था, उनको मैं कोई दोष नहीं देता, कि वे दूसरे दिन वहां जाएंगे और पूरी व्यवस्था को, जो वहां पर परेशानी हो रही है, उसको देखेंगे। वह परेशानी तो थोड़ी बहुत ठीक भी हो

जाएगी! किसी को दवा नहीं मिली, सही समय पर पानी नहीं मिला। वह अलग बात है। लेकिन इतने लोगों की जान चली गयी यहां बोलने के बावजूद भी! सरकार को एडीक्वेट अरैंजमेंट करना चाहिए था। आज सरकार कह रही है 7 नम्बर पैराग्राफ में कि Government is determined to continue the Amarnath Yatra. ठीक है, होनी चाहिए। आतंक के सामने सिर झुकाने से काम नहीं चलेगा। With renewed security measures. आउटरेजियस था आपने ऐसा बोला। एनादर ग्रुप आफ मिलिटेंट्स आ गया। आपने पैरा नम्बर दो में कहा है, a group of terrorists। जब उससे मुठभेड़ भी हो गयी, हमारे सुरक्षा बल के लोग भी मारे गए - उनको रोकने के लिए, बाधा देने के लिए, बचाने के लिए जाने में - मैं उनके लिए भी, उनकी अफसोसनाक मौत के लिए और उनकी दुखद स्थिति पर सुरक्षा बलों और उनके परिवारों के साथ अपने को बावस्ता करता हूं। कितने लोग आए थे जब मुठभेड़ हुई? थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए था। भागने के बाद या मारे जाने के बाद मिलिटेंट्स के कितने औजार, शस्त्र निकले यह तो है यहां पर। लेकिन जो 6 बजकर 45 मिनट पर हुआ उसमें कितने का गिरोह आया था? मैडम, इसके साथ आप देखेंगी कि यह बड़ी योजनाबद्ध तरीके से किया गया। एक ही दिन में 6-7 घटनाएं - एक दिन-रात के अंदर, एक के बाद एक, अलग अलग टारगेट्स, डिफरेंट प्लेसेज, डिफरेंट टारगेट्स। यात्री भी, वहां के लोकल भी और सुरक्षा बल भी मारे गए। दूसरी तरफ हमारे इमिग्रांट वर्कर्स जो ज्यादातर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे, जो ईंट भट्टों के अंदर थे, वहां भी अटैक किया, वे गरीब भी मारे गए। लोकल रेजीडेंट्स भी मारे गए है। तो इस तरह से अलग अलग टारगेट्स चुने गए। हो सकता है एक ही ग्रुप ने सेंट्रलाइज्ड प्लेस पर किया हो, हो सकता है एक सेंट्रलाइज्ड प्लान हो और अलग अलग एक्जीक्यूटर्स हों। तो ऐसा है। आप जब वार्ता करेंगे और वार्ता करनी ही चाहिए, चलनी ही चाहिए, उसे रोकने वाले जो लोग हैं उनसे आप किस तरह से निपटेंगे? सिर्फ आप रिन्यूड अरैंजमेंट होगा और सिक्योरिटी का अरैंजमेंट होगा यह बात नहीं कह सकते हैं। आपको थोड़ा और विस्तार से सदन को विश्वास में लेकर यह कहना पड़ेगा कि ऐसी घटना का रिकरेंस हम नहीं होने देंगे। कम से कम जब तक यह बातचीत चल रही है तब तक पीस के माहोल पर हो, एक पाजिटिव उसका कुछ नतीजा निकले, पूरा देश इसके लिए इंतजार कर रहा है। मैडम, मैं खत्म ही करूंगा लेकिन मेरे दो-चार इश्यूज हैं। उसमें एक तो है कि जम्मू में हमने रोक दिया। सरकार ने यह कहा कि वहां जो हमले होने थे उनको रोक दिया गया। गृह मंत्री जी हमें यह बताएं कि वहां जो सुरक्षा का प्रबंध था राजा हरीश चन्द्र स्कूल में, जिस कैंप में यह हमला हुआ, वहां पर किसकी जिम्मेदारी थी? कौन लोग वहां पर सुरक्षा का काम कर रहे थे? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है वहां जम्मू काश्मीर पुलिस के लोग थे। उस रोज भी मैंने कहा। यहां उठाया भी गया कि हमेशा जब यात्री जाते हैं, ज्यादातर तो धार्मिक यात्री जाते हैं लेकिन उनके अंदर एक भाव पैदा करके भी उन्हें ले जाया जाता है। अब टेलीविजन में इंटरव्यू अगर होगा और आप देखेंगी तो मालूम होगा। मैंने खुद बात करके देखा है। लौटकर आते वक्त कुछ लोग, सब नहीं, उसके अंदर कुछ प्लांटेड होते हैं, वे अफवाहें देते हैं और अफवाहें देते देते आते हैं चाहे कुछ भी हो कि वहां क्या हुआ। उससे पूरा माहोल बिगड़ जाता है जबकि काश्मीर की समस्या के समाधान के लिए पूरे देश की एकता की जरूरत है। वहां पर जब ये पहुंचते हैं तो वहां जम्मू काश्मीर पुलिस के बारे में -हालांकि वहां सब लोग होते हैं, जम्मू के भी लोग है, काश्मीर के भी लोग हैं, लदाख के भी लोग हैं पुलिस में - लेकिन एक एंटी जम्मू काश्मीर पुलिस कैम्पेन होती है, जैसे एंटी काश्मीर कैम्पेन होती है, जैसे एंटी काश्मीरी कैम्पेन होती है जबकि जम्मू काश्मीर की पुलिस ही हिफाजत में - यह जो दस्ता

जम्मू में था - वहां उनकी सुरक्षा करने की कोशिश की गयी और हमलावरों को रोकने की कोशिश की गयी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी - सिर्फ अमरनाथ यात्रा को जारी रखने के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में दोनों तरफ से पाकिस्तान की ओर से और पाकिस्तान के एजेंटों और पाकिस्तान के पक्ष से भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कैम्पेन शुरू होगा इस पीस प्रोसेस को विशिएट करने के लिए उसी तरह से देश के अंदर भी ऐसे तत्व हैं जो यह चाहते हैं कि वार्ता के जरिए काश्मीर का मामला हल न हो, उनके जरिए एक साम्प्रदायिक भाव उठाने की कोशिश की जाएगी - उसे भी आपको रोकना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो आपके आजू-बाजू में घूम रहे हैं वे गलत दिशा देंगे और काश्मीर का जो मामला है वह सुलझने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ता जाएगा। तो आपको यह भी एक संदेश देना पड़ेगा कि हम ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटेंगे और किसी किस्म का कोई इससे राजनीतिक स्कोर नहीं कर पाए तथा वातावरण को दूषित नही कर पाए। इसकी भी आप पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र) : महोदया, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी की पूरी स्टेटमेंट देखने के बाद कुछ चीजें मालूम करना चाहता हूं। जिन लोगों ने यह हमला किया वे हमलावर कौन थे, इस विषय पर अभी तक आपको क्या कोई जानकारी मिली है या फिर इसके पीछे आईएसआई का हाथ था, यह हम जानना चाहेंगे? दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब भी अमरनाथ यात्रा का मौका आता है तो ऐसा बताया जाता है कि वहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। मुझे याद है चार-पांच साल पहले ऐसी ही परिस्थिति निर्माण हुई थी कि अमरनाथ यात्रा नही होने देंगे। ऐसी बातें वहां सभी टैरोरिस्ट कर रहे थे, सभी आतंकवादी कर रहे थे। अमरनाथ यात्रा के लिए ज्यादा लोग जाते हैं, वहां कम लोग जाने चाहिएं क्योंकि वहां उनकी सुविधा व सुरक्षा करने में कठिनाई आती है ऐसा भी सरकार की तरफ से बताया गया था। महोदया, मैं यह बात इसलिए दोहराना चाहता हूं कि हमारे यहां खुफिया एजेंसीज हैं, गुप्तचर संगठन हैं, वे कार्यक्षम हैं, फिर भी जिन लोगों ने ऐसी हरकतें करने की कोशिश की थी, तो ये कैसे और कौन-कौन लोग हैं, इस विषय पर भी हमें पूरी जानकारी होना आवश्यक है? जैसा अभी आपने यहां बताया कि शांति बहाल करने के लिए हिजबुल मुजाहिद्दीन के साथ बात-चीत शुरू होने वाली है, तो उसके बाद भी कुछ लोग शांति नहीं चाहेंगे। ऐसे जो संगठन हैं वे कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे। ऐसी रिपोर्ट आई थी। लेकिन फिर भी सतर्क क्यों नहीं हुए? ऐसी रिपोर्ट की क्या आवश्यकता थी? वैसे भी अभी तक का यदि अनुभव देखें तो पायेंगे कि कभी भी, कहीं भी शांति निर्माण करने के लिए किसी के साथ भी बात करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी तरफ से, जिनको शांति नहीं चाहिए, वे सब लोग आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कब घटे इसी में प्रयास व कार्यरत रहते हैं। यदि अभी तक का ऐसा हमारा अनुभव है, तो बड़ी जागरूकता से, कौन-कौन से एरिया में वे लोग आतंक फैला सकते हैं, कहां से वे कार्यरत हो सकते हैं, उन सभी ठिकानों का टार्गेट करके हम वहां पर आवश्यक बंदोबस्त कर सकते थे। वहां आतंक फैलाने के लिए गांवों में महिलाओं पर अत्याचार करना, बच्चों के ऊपर अत्याचार करना या फिर अमरनाथ यात्रा जैसे शुरू हुई तो वहां पर भयंकर घटनाएं होना ऐसी कोशिशें दोबारा हो सकती है। उसी के साथ-साथ दिल्ली, मुंबई या बाकी प्रदेशों के अलग-अलग हिस्सों में भी दहशत फैलाने की या कुछ अन्य कठिन समस्या पैदा करने की भी कोशिश हो सकती है। इसलिए हमें चारों ओर से सतर्क रहने की आवश्यकता थी और वहां बंदोबस्त करने की जरूरत थी। वहां पूरे बंदोबस्त क्यों नहीं किए गए, इस विषय पर आप विचार करें। यहां प्रोक्सी वार की भी बात की गयी। महोदया, यात्रा के संबंध में मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि पुराने जमाने में रामायण, महाभारत काल में लोग

6.00 P.M.

धार्मिक यात्रा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे कि श्रवण कुमार अपने माता-पिता को लेकर गया और रास्ते में राजा दशरथ के बाण से मारा गया। तो उस समय यात्रा के लिए बाहर निकलने पर समझा जाता था कि वापिस आ गए तो अपना भाग्य नहीं तो गए तो गए। उस समय वापिस आने की उम्मीद भी नहीं होती थी। लेकिन वह पुराना जमाना था, आज तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इसलिए घर से यात्रा के लिए गया आदमी गारिंटेड वापिस आएगा, इस का लोगों को भरोसा देने की आवश्यकता है, उस के लिए पूरे बंदोबस्त किए जाने की आवश्यकता है। तो क्या गृह मंत्री जी इस विषय में सदन को आश्वस्त करेंगे? धन्यवाद।

मिर्जा अब्दुल रशीद (जम्मू और कश्मीर) : मैडम, सब से पहले तो हमारे यात्री और दूसरे लोग वहां जिस तरीके से मारे गए, उस को मैं पुरजोर लफ्जों में कंडेम करता हूं। जहां तक यात्रियों का ताल्लुक है, जम्मू-कश्मीर की रियासत में पिछले 11 साल से मिलिटेंसी है और पिछले 11 साल में यात्री वहां बराबर पुर-अमन तरीके से आते रहे हैं, यात्रा करते रहे हैं और कभी कोई इस तरह का हादसा नजर नहीं आया सिवाय एक बार के जब कि मौसम बहुत खराब था। अब की बार मैं एक ही सवाल ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से करना चाहूंगा कि हिजबुल मुजाहिदीन जमात ने जो सीज-फायर किया है या जो लोकल मिलिटेंट्स हैं या और लोकल ऑर्गनाइजेशंस हैं, उन्होंने सीज-फायर किया है, लेकिन बाकी जो 10-15 मिलिटेंट्स जमाते हैं, उन में 99 परसेंट बाहर के लोग हैं या दूसरे मुल्कों के लोग हैं, तो वह क्रॉस-बॉर्डर टेरेरिज्म जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बात करने से पहले सेक्युरिटी एरेंजमेंट्स को स्ट्रेंथन क्यों नहीं किया गया जिस की वजह से ये बेचारे गरीब और निहत्थे लोगों का कत्ले-आम हुआ? क्योंकि हमें मालूम है कि बॉर्डर से इस वक्त बाकायदगी हथियार भी आते हैं आर0डी0एक्स0भी आती है और लोगों व मोर्टार भी आते हैं और सिविल वर्दी में पाकिस्तान के सिपाही और फौज भी आती है। ऐसे माहौल में मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि आप उन का कैसे मुकाबला करते हुए अपनी पीस प्रोसेस को जारी रखेंगे? वरना अगर यही सिलसिला रहा तो और भी कत्ले आम होने के खदशात हैं।

मैं एक बात यहां यह कहना चाहूंगा कि आज से नहीं पिछले 11 साल से बल्कि 50 साल से कश्मीर को जो इंटरनेशनलाइज किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान ने तीन-चार जंगें भी की हैं और ताशकंद मायदा भी हुआ है, शिमला समझौता भी हुआ है, पाकिस्तान में लाहौर एलानिया भी हुआ है और कारगिल की जंग भी हुई, तो हम कैसे भरोसा कर लें उन पर कि जितने ऑर्गनाइजेशंस यहां पर मौजूद हैं, जिन के मास्टर पाकिस्तान में बैठे हैं, वह हमें पीस प्रोसेस करने की इजाजत देंगे? मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि क्रॉस-बॉर्डर टेरेरिज्म का मुकाबला करने के लिए आप कौन से उपाय करने जा रहे हैं जिस के बाद आप पीस प्रोसेस जारी रख सकते हैं।

श्री गुलाम नबी आज़ाद (जम्मू और कश्मीर) : मैडम डिप्टी चेयरमैन साहिबा, कश्मीर हमेशा धर्मनिरपेक्षता के लिए मशहूर रहा है, चाहे आवाज़ें अलग-अलग उठी हों, लेकिन धर्मनिरपेक्षता से कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और एक कश्मीरी के नाते आज मेरा सर शर्म से झुक जाता है क्योंकि आज कश्मीर की सरजमीं पर सैकुलरिज्म का कत्ल आतंकवादियों के हाथों हुआ है और दर्जनों तीर्थ-यात्रियों को गोलियों का निशाना बनाया गया है। भले ही ये आतंकवादी

सरहद पार के हों, लेकिन यकीनन् उन्होंने हमारी जमीन का इस्तेमाल किया है। बहुत सारे सदस्यो ने बताया कि पिछले दस बरसों मे यह पहली दफा हुआ है कि जब आतंकवादियों ने तीर्थ-यात्रियो पर हमला किया है। अभी पिछले इतवार और सोमवार को मैं वहां था और मैं पूछ रहा था कि अभी तक कितने तीर्थ-यात्री पहुंचे हैं? 1,20,000 तीर्थ-यात्री पिछले इतवार तक कश्मीर पहुंचे थे। कई सालो बाद इतने जोश से लोग जहाज मे, ट्रेन में, बसों में, कारों में घूम रहे थे। इस घटना से सैकुलरिज्म को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है।

महोदय, हिजबुल मुजाहिद्दीन ने एकतरफा सीज-फायर किया, गवर्नमेंट ने उसका स्वागत किया, हमारी पार्टी ने भी उसका स्वागत किया, सभी पोलिटिकल पार्टीज ने उस एकतरफा सीज-फायर का स्वागत किया। कश्मीर में खुशियां मनाई जा रही थी, इसलिए नहीं कि उनको कोई आज़ादी मिलेगी बल्कि इसलिए कि दस साल बाद गोली और बदूक से उनको निजात मिलेगी। जब हिजबुल मुजाहिद्दीन ने एकतरफा सीज़-फायर की बात की थी, जैसा माननीय होम मिनिस्टर साहब ने अपने वक्तव्य में फरमाया है, तो कुछ घटक, कुछ संगठन खास तौर से हरकत-उल-अंसार और लश्करे तोएबा नहीं चाहते थे कि हिजबुल मुजाहिद्दीन और सरकार के बीच में बात हो। मंत्री महोदय, आपने माना है कि आपको पूरी जानकारी थी और खुफिया एजेंसियों ने भी सरकार को चौकन्ना किया था कि ये लोग, जो बातचीत के खिलाफ हैं, वे सेबोटाज करेंगे। तो मेरा होम मिनिस्टर से पहला सवाल यह है कि आपको जब यह जानकारी थी तो आपने सेबोटाज रोकने के लिए क्या कदम उठाए? मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय गृह मंत्री जी से ऐसे स्टेटमैंट की उम्मीद मैं नहीं करता था। उम्र में हमसे बुजुर्ग हैं, ऐक्सपीरिएंस्ड हैं, लेकिन पैरा 5 को पढ़कर मैं नहीं समझता कि इसे थोड़ी सी जानकारी वाला भी यह स्टेटमैंट कहा जा सकता है। पैरा 5 में इन्होंने लिखा है :-

> "The security forces had been alerted of this, and have been asked to be more vigilant. It is because of this vigilance that the security forces had foiled an attempt of the militants to attack the Amarnath pilgrims in a Jammu camp on the morning of 1st August."

कश्मीर घाटी मे 7 जगह अटैक हुआ - पहलगांव में, अच्छबल में, अनन्तनाग मे, काजीगंड में, कुपवाड़ा में, दच्छिन में, जो आपने बताया है कि किस्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट डोडा मे है और पोगल परिस्तान, यह रामबन में नहीं है, बनिहाल में है, इन तमाम जगहों पर जो अटैक हुए, वहां आपको कुछ उपलब्धि हासिल हुई होती तो मैं मानता कि हां वाकई कुछ उपलब्धि है। जम्मू में एक सिपाही, मुझे अफसोस है कि होम मिनिस्ट्री मॉनिटर क्यों नहीं करती है, रात को टेलीविज़न पर जम्मू पुलिस के एक सिपाही ने बोलते हुए बताया कि जम्मू कैम्प पर मैं अकेला डयूटी पर था, जब गोली चली और मैंने अकेले ही उसका मुकाबला किया उतनी देर तक जब तक कि एस0एच0ओ0 शहर से और कुछ पुलिस वालों के साथ नहीं पहुंचे। तो वह उस अकेले सिपाही की बहादुरी है and it was not due to the efforts made by the Government. I am very sorry to say it. This is totally out of context. जैसा मैंने अर्ज़ किया, मैं जानना चाहता हूं कि उस सेबोटाज को रोकने के लिए, जो आपने बताया है, यह बिल्कुल आउट आफ कांटेक्स्ट है, तो उस सेबोटाज को रोकने के लिए आपने क्या इकदामात् किए जब हिजबुल मुजाहिद्दीन ने एकतरफा

सीज़-फायर किया? मुझे अफ़सोस है कि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, मैं दूसरे सदन की डिबेट भी टेलीविज़न पर सुन रहा था।

महोदया, सबसे बड़ा मुद्दा जो छूट गया है, वह मेरे ख्याल में यह है कि जब हिजबुल मुजाहिदीन ने एकतरफा सीज़फायर का ऐलान किया तो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट को भी रिस्पांड करना था। क्या गवर्नमेंट आर्मी को, पैरा मिलिट्री फोर्सेज को, स्टेट एजेंसीज को चुपचाप यह नहीं बता सकती थी कि हमने भी सीज़फायर कर दिया है? लेकिन पूरे 3-4 दिन लगातार यहां से भी और जब मैं श्रीनगर गया शुक्रवार, शनिवार और इतवार को लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, सबके स्टेटमेंट आ रहे थे कि हमने भी सीज़फायर कर दिया है। क्या टेलीविजन पर और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर सरकार की तरफ से ऐसा ऐलान करने से कि हमने भी सीज़फायर कर दिया है, हमने उन आतंकवादियों को जो इस बातचीत के खिलाफ थे, उनको हमने दावत नहीं दी कि हमने हथियार छोड़ दिए हैं, आइए, आप जो मरजी हो, कर लीजिए? इसीलिए उन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स का इस्तेमाल किया। अगर सीज़फायर आपको करनी थी तो भी सिक्योरिटी फोर्सेज को और आर्मी को टेलीविजन पर यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं थी, इसके बारे में रेडियो पर ऐलान करने की जरूरत नहीं थी। यह प्रसारण एक बार नहीं, दो बार नहीं, सुबह से रात तक, 24 घंटे तक यह चलता रहा, आपने नहीं सुना, मैंने सुना है।

श्री सतीश प्रधान : मैंने भी सुना है लेकिन उन्होंने कहा था हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में ही ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीर में और हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में आज मिलिटेंट्स आर्मी की वर्दी पहनकर और उनके जैसे स्टार लगाकर हमला करते हैं। आज कोई भी आदमी चाहे वह तोयबा का हो या हरकत का हो, वह कहेगा कि मैं हिजबुल मुजाहिदीन का हूं, मुझको मत छेड़ो, मुझको जगह दे दो? कोई मैडल लगे है कि कौन मिलिटेंट हरकत का है, कौन तोयबा का है, कौन हिजबुल मुजाहिदीन का है? इस तरह से टेलीविजन के जरिए जो सीज़फायर की बार-बार घोषणा हुई, मैं समझता हूं कि उसने भी उनको चौकन्ना किया है कि हम चुप करके बैठे हैं, आप आओ, जो मरजी है कर लो। यह जो टेलीविजन के जरिए और मीडिया के जरिए सीज़फायर का ऐलान किया गया, इस गलत निर्णय से जो कत्ल हुए हैं, क्या इस गलत निर्णय की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है या नहीं?

माननीय उपसभापति महोदया, मैं होम मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जिन आतंकवादी संगठनों ने बातचीत का विरोध किया है और जो आज की हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं, क्या केन्द्रीय सरकार अब दोबारा से फौज और स्टेट पुलिस को हुक्म देगी कि उन संगठनों का सफाया करने के लिए किसी भी किस्म की नरमी न बरती जाए। इसको आप टेलीविजन पर कहें, न कि ऑर्डर्स दें ताकि वे सतर्क रहें।

महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ज्यों-ज्यों हिजबुल मुजाहिदीन और सरकार के बीच बातचीत आगे बढ़ेगी त्यों-त्यों आतंकवादी अपनी गतिविधियां तेज करेंगे, लेकिन हम सब इस मत के हैं कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमको आगे बढ़ना होगा। इसके लिए क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार की मदद करने के लिए मजीद सिक्योरिटी फोर्सेज और आर्मी का बंदोबस्त करेगी?

महोदया, मेरा आखिरी निवेदन यह है कि ये आतंकवादी जो बातचीत के खिलाफ हैं, ये आज फ्रस्टेटेड हो गए हैं कि इनको कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए अब वे सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला करेंगे। इसलिए सॉफ्ट टारगेट्स पर भी नज़र रखी जाए, इसके लिए होम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, यह मैं उनसे जानना चाहता हूं।

SHRI SWARAJ KAUSHAL (Haryana): I have read the statement of the hon. Home Minister. I have an unflinching faith, I have an inherent faith, in a dialogue. But when I read the statement, I was quite disappointed. The Home Minister in his statement has said, "Consequent on the cease-fire declaration made by the Hizbul Mujahideen.." Whom do you have cease-fire with, Mr. Home Minister? You have cease-fire only with a sovereign country? How can you use this word? I do not want to hear this word.

How somebody who is committed to the unity and integrity of India, could ever use this word in any negotiation or a dialogue? I am very sorry to read this word. I am very sorry to hear this word. You used this word, Mr. Home Minister, I am sorry; you have gone wrong on the basic parameters of the dialogue? When you go wrong on the basic parameters of the dialogue, I am sorry, what is the use of any dialogue. Once you use this word, how do you tell them, finally, how do you tell that underground group that we will accept no settlement outside the Indian framework? I have never used the word 'Indian Constitution.' It has been used so often. It normally conveys a feeling that you are really not ready for a dialogue because the Constitution provides for an amendment. You can amend the Constitution, under article 368. But how could you use this word, Mr. Home Minister? Will you please answer this? When this was done, I expected a statement from the hon. Home Minister, but this was not done. This is an important announcement. You should have made a *suo motu* statement on the floor of the House. But I have to read this because there has been an incident in Kashmir and it is an unfortunate one. When you start with this parameter, where do you arrive at? How will you tell this underground group that we will not accept any settlement beyond the Indian Union, beyond the Indian set up? Let me tell you one more thing. The responsibility of Hizbul Mujahideen towards the maintenance of peace and harmony in Kashmir is equal because they say that they represent the majority of the underground groups and, I know, your assessment is very right that 95 per cent of the insurgents of Kashmiri origin belongs to this organisation. That is a very happy sign. But their responsibility towards the maintenance of peace is equal. Otherwise, if you arrive at a settlement,

how will you ensure peace? How will you ensure the implementation of the accord, if they cannot maintain peace and harmony while the dialogue is on? My warning to the Government is, as the dialogue progresses, there may be more and more of such incidents. Do you assure this House that there would be no recurrence of such incidents when a settlement is insight, with the progress of the dialogue? Since 1998, 7,600 people have been killed as a result of terrorist violence. I do know why we are so helpless? Why this nation of one billion, and a nuclear power, is so helpless? Why this country such a helpless nation? Mr. Advani, we expect something from you. We want to see the 'iron man' in the hon. Home Minister. Please prevent the recurrence of such incidents. You may go ahead with the dialogue. Please make sure that such incidents do not occur on the territory of India again. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Obaidullah Khan Azmi. I have got a lot of names because the issue is very serious. खाली आप पर नहीं जितने हैं जो आगे भी आने वाले हैं इसलिए मैं बोल रही हूं। अगर आप क्वेश्चन करलें तो सभी [illegible] हो सकते हैं वरना मुझे बंद करना पड़ेगा कहीं न कहीं जी।

*मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी (बिहार) : शुक्रिया मैडम् सदर साहिबा. सबसे पहले मैं जम्मू एंड कश्मीर में जो यह गमनाक हादसा हुआ है उसमें जितने लोग भी मारे गए हैं उन तमाम लोगों के लिए अपना खिराज-ए-अकीदत पेश करता हूं। और बर्बरियत और हैवानियत की पुरजोर मजम्मत करता हूं। मैडम्, एक बात तो बड़ी साफ है जिसको सरकार भी बार बार कह चुकी है और हर हिन्दुस्तानी बच्चा इस बात को अच्छी तरह से जानता है और उस दुख दर्द के तदारुक की वह तलाश करता है वह यह कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान को खोखला करने के लिए, हिन्दुस्तान को कमजोर करने के लिए और मुकम्मल तौर पर हिन्दुस्तान हमेशा बदअमनी का शिकार रहे और यह बदअमनी फैलाने के लिए दिन-रात अपनी योजनाएं बनाता रहता है और साजिश करता रहता है। उसी साजिश का एक हिस्सा अमरनाथ यात्रियों के कत्ले गारतगिरी की शक्ल में हमें देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की गर्दन शर्म से झुके या न झुके, इन्सान और इन्सानियत की गर्दन इस अल्मनाक हादसे से जरूर शर्म से झुकती है। मगर जिन लोगों ने इंसानियत को परे रखकर हैवानियत और बर्बरता का रास्ता अपनाया है, उनसे किस तरह से निपटा जाए यह हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को और हर हिन्दुस्तानी शहरी को सोचना है।

मैडम, एक साइड हिजबुल मुजाहिदीन हमारी हुकूमत से गुफ्तगू कर रहा है और मैं स्वराज कौशल साहब की इस बात से मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूं कि यह कोई और मुल्क नहीं है, हमारे ही मुल्क के कुछ गुमराह लोग हैं जो पाकिस्तान की शह पर हिन्दुस्तान में गुमराही का शिकार बने हुए हैं। उनसे गुफ्तशनीद करने के लिए यह बात जरूर जहन में रखी जानी चाहिए थी।

---

*Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate

कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, अफगानी ग्रुप हैं, पाकिस्तानी ग्रुप हैं और भी कोई दूसरा-तीसरा ग्रुप है जो मुसलसल पाकिस्तान की शह पर हिन्दुस्तान को खोखला कर रहा है, उसकी एक्टीविटीज पर बराबर नजर रखी जानी चाहिए थी। कहीं न कहीं हमसे गफलत जरूर हुई है जिसका नतीजे में अमरनाथ यात्रियों का यह दर्दनाक मामला सामने आया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो मुल्क मजहबी भावनाओं से जुड़ा हुआ न हो। अगर इसी तरह से मजहबी यात्राओं पर और मजहबी स्थलों पर जाने वाले लोगों के साथ जो जुल्मो-सितम का तौर-तरीका अपनाया जा रहा है, मैं तो समझता हूं कि न तो किसी मजहब ने इस बात की इजाजत दी है और न किसी मुतमद्दीन इंसानियत और तहजीब के गहवारे इस बात की इजाजत देते हैं।

मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिजबुल मुजाहिदीन परदे के पीछे जो सीज फायर के नाम पर पाकिस्तान अपनी किसी साजिश को कामयाब बनाना चाहता है क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन का हैड-क्वाटर हिन्दुस्तान में नहीं है पाकिस्तान में है। यह जो हिजबुल मुजाहिदीन है इसके जो लीडरान हैं, इन लीडरान के हैड आफ दी डिपार्टमेंट का नाम सैय्यद सलाहुद्दीन है जो हिन्दुस्तान में नहीं रहते पाकिस्तान में रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह से कोई साजिश करके हिजबुल मुजाहिदीन को आगे लाया हो और हमारी हुकूमत की आंखों में धूल झोंक रहा हो। हमारे होम मिनिस्टर साहब इस पर से परदा उठाये तो ज्यादा बेहतर होगा। जब अटल जी की बस यात्रा हुई तो उस वक्त भी राजौरी में 29 आदमियों को मार दिया गया, जब बिल क्लिंटन साहब हिन्दुस्तान में मेहमान बनकर आ रहे थे तो उससे एक-दो दिन पहले काश्मीर में खूनी ड्रामा खेला गया था। अब जब मजहबी यात्रा में लोग गए हैं उनके साथ यह नापाक तौर-तरीका अपनाया गया है उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। जब गवर्नमेंट कोई शांति का प्रोग्राम बनाती है तब इस तरह की अशांति पैदा कर दी जाती है। आखिर इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? उनके हाथ तोड़ने के लिए हुकूमत अपनी कौन-सी वाजाह पालिसी मुल्क के सामने रखना चाहती है, हुकूमत को इसका खुलासा करना चाहिए।

मैडम, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आपका हुक्म सर आखों पर रखता हूं। इख्तसार से काम ले रहा हूं। ये हथियार कहां से आ रहे हैं? क्या यह आसमान से हिन्दुस्तान में टपक रहे हैं या जमीन उगल रही है? यह बहुत ही अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब देना होगा और यह बताना होगा क्योंकि इससे हमारे सुरक्षा बलों का हौंसला घटता है और बढ़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सुरक्षा करने वालों का हौंसला आप बढ़ाते रहें और सुरक्षा करने वाले हमारे देश का हौंसला घटाते रहें, यह कोई देश के साथ बहुत बड़े मुहब्बत की अलामत नहीं है। सवाल यह है कि वहां पर हमारी बार्डर सेक्योरिटी फोर्स लगी हुई है, वहां पर हमारी फौज लगी हुई है, वहां पर हमारी पुलिस लगी हुई है, फिर भी पाकिस्तानी आतंकवादी किस चोर दरवाजे से यहां पर आते हैं और कहां से यह हथियार लाते हैं? फिर यह हथियार देसी हैं या विदेशी हैं? अगर विदेशी हैं तो यह हथियार कौन ला रहा है, किसके जरिए से आ रहे हैं, कौन पैसा खा रहा है, कौन मादिरे-वतन की इज्जत को बेच रहा है? इस नकाब को जरूर उठाना चाहिए ताकि हिन्दुस्तान की इज्जत बेचने वालों को अच्छा सबक सिखाया जा सके।

मैडम, इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोग इस यात्रा में थे, जिन लोगों को मारा-पीटा गया है, हमारा दुश्मन यह चाहता है कि हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, हिन्दुस्तान के लोगों के आपसी सद्भाव को खत्म करने के लिए, हिन्दू के नाम पर, मुसलमान के

नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर, बौद्धिष्ट के नाम पर, हिन्दुस्तानियों को काटा और मारा जाए।

'यह न हिन्दू का कत्ल है, न मुसलमान का कत्ल है,
ऐ दुश्मनाने हिंद, यह इंसाँ का कत्ल है।'

यह इंसानियत का कत्ल हुआ है और हम सभी हिन्दुस्तानी हैं। इसमें हिन्दू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मगर अपने मादिरेयतन की इज्जल के लिए हमारी हिन्दुस्तानियत की एकता को तोड़ने के लिए हमें मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, ईदगाहों के नाम पर, मजारों के नाम पर आपस में लड़वाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्या हुकूमत इस साजिश को पूरे देश में असफल करेगी, उन्हें नाकाम करेगी? हुकूमत को इस बात का वाजे तौर पर जवाब देना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री रामदेव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदया, सबसे पहले मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से पिछले 24 घंटे में जो 80 लोग जम्मू-कश्मीर में मारे गये हैं, उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं, दुख व्यक्त करता हूं। महोदया, हिजबुल मुजाहिदीन के लीडरों को जब छोड़ा गया तो देश में एक संदेश गया, एक आशा की किरण जगी कि शायद भारत सरकार के पास एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से जम्मू-कश्मीर में शांति स्थापित हो जाएगी। जब हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से एक तरफा सीज़ फायर की बात की गयी तो एक और उम्मीद जगी कि शांति का डॉयलॉग, शांति का समझौता जम्मू-कश्मीर में हो रहा है। गृह मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन के साथ बातचीत से कुछ और जो मिलिटैंट्स ग्रुप्स थे, उनको धक्का लगा और उम्मीद की गयी कि वह जो मिलिटैंट ग्रुप्स हैं, वे अटैक करेंगे, उनकी मिलिटैंसी और बढ़ेगी - यह बयान में आया है। महोदया, कहां कमी रह गयी, किस स्तर पर कमी रह गयी कि कुछ ही घंटों के अंदर 80 लोग मौत के शिकार हुए? क्या इंटैलीजैंस में कमी रह गयी? क्या इंटैलीजैंस के लोगो ने हमें सही रिपोर्ट नहीं दी? क्या हमारा बंदोबस्त पुख्ता नहीं था कि दो मिलिटैंट्स ने किचन में घुस करके ए.के.-47और ए.के.-57 राइफल लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर लोगों को मार दिया। महोदया, सरकार इस बात से नहीं मुकर सकती कि सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह विफल रही है। इस तरह से अगर सुरक्षा में कमी रही तो जम्मू-कश्मीर में शांति और अमन कब तक आएगा, उसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो इस देश की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जम्मू-कश्मीर की जो सरकार है, जो एन.डी.ए. की घटक सरकार है, को कॉन्फीडेंस में लिया जा रहा है? हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों को छोड़ा गया तो क्या देश की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको कॉन्फीडेंस मे लिया गया? देश को कॉन्फीडेंस में लेना चाहिए। यह बहुत बड़ा मसला है और कोई आज का मसला नही है, इस देश के लिए बहुत बड़ा मसला है और हम इस मसले के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सैंटीमैंट्स इस मसले के साथ जुड़े हुए हैं। अगर यह मसला हल हो जाता है - हम चाहते हैं कि यह सरकार इस मसले को हल करे, हमारी शुभ कामना है, हमारी पार्टी की शुभकामना है - मगर हल करने के लिए इन्हें हमें भी विश्वास में लेना पड़ेगा, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्हें भी विश्वास में लेना पड़ेगा। पूरा देश इस मसले को हल करने के लिए इनके साथ है। पूरी ताकत से जो मिलिटैंट ग्रुप्स हैं, जो हत्यारे हैं, पूरी ताकत से और कठोरतापूर्वक उनका मुकाबला करना पड़ेगा और इसके लिए मैं पुनः एक बात दोहराना चाहता हूं

कि पूरे देश को आप विश्वास में लीजिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको विश्वास में लीजिए। निश्चित रूप से हम सब आपके साथ हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I have lots of names before me and still more names are coming. In the morning itself I had said that once a discussion is going to take place, whether it is on a legislation or on a statement, prior intimation is given. Everybody knew that there is going to be a statement because we had taken out a Supplementary List of Business. Originally, we had only seven names. We would have at the most allowed two, three more names. But while the discussion is going on, people get new ideas and they keep sending their names. It is not a good procedure. People should be serious. *(Interruptions)* Please, one minute. People should be serious. You knew that there is going to be a statement. You knew in the morning itself that there is going to be a statement because the Home Minister promised to make a statement. I myself had announced that the statement will be made here before 5 o'clock or around 5 o'clock. The Home Minister might be having some other business. It is fine for the Members that they speak and go out of the House. But the Home Minister has to sit till he replies to all the questions. Therefore, to have a good discussion, to have a meaningful reply, which will be prominent report in the newspapers also, we should know what our responsibility is. In future, please give the names well in time. Now I am getting *parchees* after *parchees* that 'I want to speak.' Now, the number of Members who want to speak has increased to 27. The Home Minister has to pilot a very important Bill on Jharkhand, in the Lok Sabha. He should be freed from here as early as possible. He has to go there. Besides, most of the Members are saying the same thing. Because nothing new can come out of the two-pages statement over the situation in Kashmir. I would request those whom I will call now, to confine themselves questions which have not been asked and not to repeat the same questions.

DR. M.N. DAS (Orissa): Madam, since this is a very serious matter, can we postpone the debate to tomorrow or the day-after-tomorrow?

THE DEPUTY CHAIRMAN: No; I don't think a serious matter should be postponed because, in that case, it loses its sharpness, it loses its response. The Home Minister has already replied in the Lok Sabha. Why do you want to lose the importance of a discussion in the the Rajya Sabha? Because I feel, a much higher level discussion is taking place here.

I was watching the proceedings in the other House. I do not want to cast any aspersions on the other House. We should listen to the Home Minister. Nothing more is going to come out other than that we have great sympathy and heart for the people who have been killed. It is the concern of the whole House. The whole country is united on that. Now, Shri Duraisamy.

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamil Nadu): Thank you, Madam. I will not take much time. We are all deeply anguished over the killing of innocent Amarnath pilgrims, labourers and CRPF jawans. Madam, enough security forces, police, CRPF, and Army have been provided for the Amarnath yatra. We want to know from the Home Minister how it happened? That is the main issue. The Hizbul Mujahideen has declared a ceasefire after a long time. In the incidents, which have happened at six different places, 80 lives have been lost. We should apply our mind as to what is the motive behind it? Definitely, another militant group might have been involved. I differ with other hon. Members. We cannot disrespect the services rendered by the Army, the CRPF and other forces. But the hon. Home Minister should give clear cut instructions that there should be proper coordination amongst the three groups to avoid such incidents in future. I request the hon. Home Minister, through you, to give instructions that the Army and the CRPF should take more care in future to avoid such incidents. I appreciate the hon. Home Minister for taking relief measures in time. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN : You should take a clue from him and be brief.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala) : I will be confining myself to the statement alone. Madam Deputy Chairperson, I too condemn the inhuman and brutal killings of 80 innocent people of our country and also express my heartfelt condolence to the members of the bereaved families. Madam, I would like to say that this has happened because of the lapses in the security arrangements. The statement of hon. Minister itself shows that there were lapses in the security arrangements, and adequate security was not provided in the camps, especially because firing took place in the camps where these Amarnath pilgrims were staying. It has been well expressed in the statement itself that adequate security has not been provided in the camps. Madam, when this Amarnath Tirth Yatra is going on, the utmost priority of the Government was to take into consideration the developing political situation in the State of Jammu & Kashmir. Madam,

the autonomy resolution passed by the State Assembly of Jammu & Kashmir, the stand taken by the All Party Hurriyat Conference and the latest political development, which is very pertinent to note, about this Hizbul Mujahideen declaration, their ceasefire; all these political developments had taken place during the last 20 days or the last one month. Madam, when this Tirth Yatra is going on, abundant care has to be taken by the Government or the concerned authorities to give adequate protection, at least, to the pilgrims. But here, it is very evident from that statement that there were lacunae and lapses on the part of the Government, whether it is the Army or the paramilitary forces or whoever it may be. The point is that proper security arrangement has not been provided.

Madam, my second clarification is about the offer that has been made by Hizbul Mujahideen and the Government's positive response to this offer. I do not know whether it is proper to say this at this juncture because peace talks are going on. If it is not going to affect the peace talks, would the Minister reply to my question? Madam, the Minster has mentioned in paragraph 5 of his statement, and I quote, "consequent on the cease-fire declaration made by the Hizbul Mujahideen and the Government's positive response to this offer ...." Madam, Deputy Chairperson, we are still in the dark as to what is the offer that is made by Hizbul Mujahideen and what is the Government's positive response to this offer. We are still in the dark. I would like to know whether it could be discussed in the House in future. It is being said by one official of the Government that the whole discussion would be take place within the farmework of the Constitution, but the spokesman of the Hizbul Mujahideen specifically stressed that as far as they are concerned, there is no Constitution, no framework, rules and regulations for the discussion. What offer has been made by Hizbul Mujahideen? Will the Minister clarify this point? With these words, I conclude. Thank you, Madam Deputy Chairman.

DEPUTY CHAIRMAN : Chaturvediji; not speaking. Shri J. Chitharanjan.

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Madam Deputy Chairperson, I strongly condemn the ghastly attack against the brick-kiln workers and other innocent citizens and the personnel of the security forces. I condole the death of these persons and I also express my heartfelt condolences to the members of the bereaved families. Madam, I do not want to speak much on this. However, I would like to draw the attention of the hon. Minister to paragraph 5 of the statement. I quote, "Consequent on the

cease-fire declaration made by the Hizbul Mujahideen and the Government's positive response to this offer, there have been reports that some of the other militant outfits with a large component of foreign mercenaries who were unhappy about the offer of Hizbul Mujahideen may create problems and escalate violence." Madam, I would like to state that in the present day condition that is prevalent in the State of Jammu & Kashmir, even when one group declares a cease-fire, there is no meaning to that because so many other militant groups are there. They were not in agreement, or else they could have declared a cease-fire at the same time. But most of the other groups are not in agreement; and, besides there is a powerful force working behind all these groups. Therefore, not much of political wisdom is required to arrive at the conclusion that we should be more cautious when this development takes place. But I find from the statement itself that the Government and the security forces were not that vigilant. Take, for example, the incident that took place in Pahalgam. Pahalgam is a place where pilgrims are allowed to camp. Thousands and thousands of pilgrims are allowed to go and camp there. Naturally, elaborate security preparations will be there. To such a place, at about 6-45 p.m. or 7-00 p.m., how can a number of terrorists come in a car, get down at that place, then go to the *langar* where hundreds of people were taking food and fire at them? From this incident, it is quite clear that there was no vigilance on the part of the security forces. Or else it would not have happened there. Perhaps, it might have happened at the brick kiln, but it would not have happened there. Therefore, this incident shows that there was lack of vigilance on the part of the security forces. If at all they were alerted, there was delay in alerting them. Perhaps, it might be after some incident had occurred.

This is all I have to say. Therefore, the hon. Minister may explain why it so happened at that place and what arrangements will be made to ensure security.

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I appeal to you to give a chance to Telugu Desam also.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, it is coming. But her name is not there. Mr. Ramachandraiah.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Did you call my name, Madam?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I did. You are there.

He was pointing to the lady Member. So, I thought that he wanted to give a chance to a woman. I looked at her. Then I looked at the name. Please speak.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Madam, I condemn the dastardly and cowardly act. I do not want to go into how it has happened. I am fully confident that the Government has got the capacity to protect our borders and our people.

In spite of the presence of the CRPF, the regular army and the BSF, it is very difficult to provide one-to-one protection in the country. Had it been a fight against the militants within the country, it would have been solved a long time back. But the crux of the problem is that it is getting financial and armament support of an inimical neighbour. This is linked with our foreign policy also. It is not an internal problem, I should admit. They are trying to create strife in the country, disturbances in the country, for the obvious reasons best known to everybody.

I want to seek clarifications from the Home Minister. The Prime Minister is visiting the United States. Can we get an assurance from the United States that Pakistan would be declared as a terrorist State? Can we demand of the United States that it should influence the IMF not to finance Pakistan? These are all the reasons. Pakistan is enriching itself to perpetuate the border terrorism. So, the solution does not lie within the country. It lies in stopping Pakistan from encouraging the terrorism in our country. There seems to be a twist in our relations with the United States. I would like to know to what extent we have benefited from it. It is high time we utilise these relations with the United States to contain Pakistan from pursuing these activities. I say this because Pakistan, with the help of finances obtained from the I.M.F. and the World Bank, is financing the I.S.I. operations here in India. For your information, even fake currency is being pumped into our economy, in addition to a huge amount of money that is being funded to these agencies. The genesis of the problem lies there, not here. Therefore, the Home Minister should take all these things into consideration and evolve our foreign policy in such a manner that it is beneficial to our country. Until peace is restored, there cannot be any development in the country.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Madam, my party joins other Members in extending its condolences to the bereaved families and condemns these dastardly acts in the strongest terms.

Madam, the Kashmir Assembly had recently passed the Autonomy Resolution. I would like to know whether this incident has any connection with that Resolution. The narration of the events suggest that only innocent persons pilgrims and labourers - were killed. I would like to know whether these people want to achieve their objective of autonomy in Kashmir through these acts. Is it that the Kashmir Government is behind these activities?

Whenever there are such killings, a statement is made in the House and Members are allowed to express their concern. It has become a regular feature in the House. I would like to know what steps the Government is going to take in this regard, to prevent such incidents.

In these incidents 80 lives have been lost just within a night. I would like to know what part our intelligence network is playing to contain these. Why were they not able to foresee that something like this might happen during this time.

Madam, for the last 50 years, we have been continuously witnessing this problem. I would like to know whether our Government is going to take the opinion of the Kashmiri people to find out whether they want to be part of India or they want to separate. I am given to understand that a highest judicial officer of this nation has expressed the view that the Kashmiri people do not want to be under the Indian Constitution and that they want to have a separate constitution. I would like to have an answer from the Home Minister in this regard.

SHRI T.N. CHATURVEDI (Uttar Pradesh): Madam, this is irrelevant.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are not discussing the question of autonomy. Nor are we discussing the opinion of the unknown person. This would send a very wrong message outside. I do not think the House will permit this to be spoken or replied to.

श्री विजय जे. दर्डा (महाराष्ट्र) : महोदया, जो दर्दनाक और शर्मनाक घटना घटी है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी थोड़ी है। मैं इस सदन का ज्यादा समय न लेते हुए कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा।

क्या जो तीर्थ यात्री यहां पर गए थे उनको आपने विश्वास नहीं दिलाया था कि उनकी यात्रा सुरक्षित होगी और अगर आपने उनको यह विश्वास दिलाया था तो फिर यह घटना कैसे घटी? क्या इस बात की हमें जानकारी नहीं थी? जो घटनाएं वहां पर घट रही हैं उन सब की जानकारी देने में हमारी सारी एजेंसियां इसमें नाकामयाब रहीं? यह कैसे हुआ, हमारे पास इसकी जानकारी थी या नहीं? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि कश्मीर में अभी तक करीब 35000 लोग मारे गये हैं। क्या आदरणीय गृह मंत्री जी आप इसका ब्रेक अप देंगे कि उनमें से कितने कश्मीरी पंडित

थे, कितने हमारे जवान मारे गये, कितने पुलिस के लोग मारे गये, कितने हमारे मुस्लिम भाई मारे गये ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान से लगातार आतंकवाद मचा कर हिन्दू और मुस्लिम को गुमराह कर रहा है, मार रहा है और जो उन्होंने यहां पर नंगा नाच शुरू किया है, वह दुनिया को बता सकें। मैं चाहूंगा कि जो घटना घटी है, उससे सारा राष्ट्र दुखी है। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह उनको सुरक्षा नहीं दे सकी? क्या ऐसी सरकार विश्वास दिला सकती है कि तीर्थ यात्री तीर्थ यात्रा पर जाएं? इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आदरणीय गृह मंत्री जी इसका जवाब दें। धन्यवाद।

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे (महाराष्ट्र) : माननीया उपसभापति महोदया, आतंकवाद का सिलसिला वर्षों से चलता आ रहा है और दिन प्रति दिन हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। हर वर्ष यह यात्रा होती है। हजारों यात्री उसमें भाग लेते हैं। हर एक को संरक्षण देना मुश्किल है, मैं समझ सकता हूं लेकिन जहां सैकड़ों के ऊपर यात्रियों के केसेज हैं, इसमें जम्मू का उल्लेख आया है, इन केसेज में जिसे पूरा का पूरा संरक्षण कहते हैं वह था क्या, यदि नहीं था तो क्यों नहीं था, मैं यह जानकारी चाहता हूं? धन्यवाद।

उपसभापति : रामूवालिया जी आप भी संक्षेप में पूछ लीजिये।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं जाती अनुभव से यह महसूस करता हूं कि यह जो हिजबुल मुजाहिदीन से बातचीत हो रही है, इसको इस देश को बहुत नाजुक और गम्भीर हो कर लेना चाहिये। बातचीत के लिए आगे आना, यह कोई कम बहादुरी नहीं होती। मैंने देखा है कि जब संत लौंगोवाल बातचीत के लिए आगे आए थे तो उनको पहले ही दिन कत्ल कर देने की बात कह दी गई थी। इसलिए बहुत विशेष, बहुत नाजुक और बहुत गम्भीर स्थिति में हिजबुल मुजाहिदीन बातचीत के लिए आगे आए हैं। सरकार भी बात कर रही है तो इस स्थिति में सरकार को भी बातचीत के वक्त में मदद देनी चाहिये, सपोर्ट करनी चाहिये और पूरा देश उनके साथ है। मैदान, बात फील्ड में प्रेक्टीकल देखने के बगैर कर लेनी आसान है। यहां एक गवर्नर साहब थे। वह पहले राज्य सभा के सदस्य थे। मुझे बाहर घेर लिया, बोले पंजाब में आतंकवादी आदमी को कत्ल कर के निकल कैसे जाते हैं। मैंने कहा एम.पी. साहब वहां हालात बहुत खराब हैं। आप हर चीज सरकार पर मत थोपिए कि कैसे निकल जाते हैं। निकल गए। जब बरनाला की गवर्नमेंट थी तो हम अकाली दल में थे। संयोगवश चार महीने के बाद वे ही एम.पी. पंजाब में गवर्नर हो गए। उनका शुभ नाम श्री वीरेन्द्र वर्मा है। अभी भी है। जब ऐसे ही लोग मार मार कर निकले, तो मैंने महामहिम राज्यपाल से पूछा, सर अब आप गवर्नमेंट के हेड हैं, अब उसी तरह से लोग मारकर कैसे निकल जाते हैं। इसलिए मेरी एक राय है कि इस देश को ऐसी मुसीबत में घबड़ाहट में नहीं आना चाहिए, एक बात।

दूसरी बात, अब किसका कसूर है? गुलाब नबी जी ने भी कहा, औरों ने भी कहा, दोष किसका है? हमारा पड़ोसी बड़े डिटरमिन्ड वे से, डेसपरेट वे से तोड़ रहा है। मुझ एक ही बात का खदशा है जिसको सभी ने यहां अपहोल्ड किया कि कहीं इसका बैकलैश न हो जाए। मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा। उसकी पीड़ा मेरे दिल में जिंदगी भर रहेगी कि जब कत्ल कोई करता था लेकिन सभी सिखों को टेरोरिस्ट कहा जाता था और बड़े बड़े लोगों को यहां तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि पर भेंट करने गए गैरकांग्रेसी और गैरअकाली सिखों पर भी शक किया गया।

मै एक बात कह रहा हूं। एक तो साफ्ट टारगेट्स वे लाएंगे। यह उनका तरीका होता है। उसका ख्याल रखने के लिए सरकार, जैसे और भी सदस्यों ने कहा, क्या कर रही है? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग बातचीत के लिए आगे आए है उनको इरिलेवेंट बनाने के लिए वे भी कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं जैसे संत लौंगोवाल को इरिलेवेंट करने की कोशिश की गयी सरकार की तरफ से, वैसी बात तो नहीं हो जाएगी और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हिजबुल मुजाहिदीन को डिमारेलाइज करने के लिए भी यह किया जा रहा है,इसके लिए सरकार की नीतियों में क्या फैसला है कि ये डिमारेलाइज न हो जाएं। धन्यवाद।

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JASWANT SINGH): I just wish to make a submission. I do not wish to intervene. it is a very important series of clarifications that are being sougnt. And the sense of outrage is palpable. By all means, hon. Members have a right to seek clarifications. The hon. Home Minister has an obligation to the other House too. I appeal, Madam, to you and, through you, to the Members, that if the clarification-seeking is for a short time, then the hon. Home Minister will be able to fulfil his continuing duty in the other House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes. Some suggestions were going to be given.

श्री अहमद पटेल (गुजरात) : महोदया, हमारे जो साथी सदस्यों ने कहा है मैं उसका रिपीटेशन नहीं करना चाहूंगा। यह वाकया जो बहुत ही खौफनाक और दिल को हिलाने वाला वाकया है, इसकी भर्त्सना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति मै अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनके जो रिलेटिव है उनके प्रति भी अपनी सहानुभूति पेश करता हूं।

मै मंत्री जी से सिर्फ दो प्रश्न करना चाहता हूं और एक सुझाव देना चाहता हूं। क्या हिजबुल मुजाहिदीन ने यह बात सरकार को कही थी कि कुछ स्थानों से मिलिट्री, पैरामिलिट्री या पुलिस को हटाया जाए या कम किया जाए? क्या यह इसी का नतीजा तो नहीं था जैसे गुलाम नबी जी ने कहा कि एक थाने पर सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबुल था। So that is number one. Number two, क्या सरकार को यह मालूम है कि यह जो हादसा हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है? क्या सरकार किसी ग्रुप को आइडेंटीफाई कर पायी है? तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जो लोग मारे गए हैं उनकी जो सूची है उसको जल्द से जल्द पेश करना चाहिए क्योंकि हजारों यात्री वहां पर गए और मारे गए लोगों के जो रिलेटिव्स हैं उनको पता नहीं है कि वहां कौन मारा गया, कौन नहीं मारा गया। एक पैनिक सा है रिलेटिव्स में। तो जल्द से जल्द यह सूची बाहर आनी चाहिए ताकि जो बाकी रिलेटिव्स हैं उनमें पैनिक न हो और जो रिलेटिव्स हैं जिनके लोग मारे गए हैं उनको वहां पर पहुंचाने का इंतजाम करना चाहिए तथा उनको जो कम्पेनसेशन है, मुआवजा है वह जल्द से जल्द देना चाहिए या तय होना चाहिए। धन्यवाद।

7.00 P.M.

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): एक-दो बाते मुझे भी करनी हैं।

उपसभापति : अभी आपके लीडर बोल चुके हैं।

श्री संजय निरुपम : नहीं, मैडम, यह तो हमारे सेंटीमेंट्स का सवाल है। बात-बात पर पार्टी की बात नहीं की जाती है।

उपसभापति : यह पार्टी नहीं है।

श्री संजय निरुपम : बात-बात पर पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए कि एक पार्टी से एक आदमी बोलेगा। हमारे भी कुछ सेंटीमेंट्स हैं। हमारे मन में भी कुछ सवाल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी से एक आदमी बोलेगा। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : संजय निरुपम जी, एक मिनट, अगर मैं आपका यह ऑर्गूमेंट मान लेती हूं तो ऐसा करते हैं कि हम हाउस में कुछ और काम कर लेते हैं। होम मिनिस्टर साहब जाकर झारखंड का बिल पास कर दें और मैं जितने लोग यहां बैठे हैं उन सबका नाम लिख देती हूं। सब अपने-अपने सेंटीमेंट्स पर 15-15 मिनट बोल दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर मैं अभी तो नहीं बोलने दूंगी, क्योंकि होम मिनिस्टर को जाना है।

श्री संजय निरुपम : ठीक है, तो पहले फिर यह तय किया जाए कि झारखंड ज्यादा सीरियस है या कश्मीर?

उपसभापति : सब सीरियस है।

श्री संजय निरुपम : नहीं, झारखंड पर रिप्लायी तो कल भी हो सकता है लेकिन इस मुद्दे पर तो आज ही चर्चा होनी चाहिए, आज ही गृह मंत्री महोदय का रिप्लायी आना चाहिए।

उपसभापति : वह रिप्लायी करने को तैयार हैं।

श्री संजय निरुपम : लेकिन हमारे मन में भी कुछ सवाल हैं, मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): लीडर ऑफ् द हाउस की अपील है।

उपसभापति : देखिए, लीडर ऑफ् द हाउस ने अपील की, पूरे हाउस का सेंस है, जवाब आज आना चाहिए, सात बज रहे हैं, उसके जवाब की कुछ अहमियत हो जाएगी और रूलिंग ऑफ् द चेयर है। मैं तो इस तरह की रूलिंग कभी देती ही नहीं। मगर हालात ऐसे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम : सब से ज्यादा खतरनाक रूलिंग तो मत दिया करें।

उपसभापति : यह कोई खतरनाक नहीं है। अगर मैं खतरनाक ...**(व्यवधान)**... संजय जी, अगर मैं अपनी अथारिटी को इस्तेमाल करती तो मैं 7 नाम के बाद किसी को बुलाती ही नहीं और उसमें कम से कम आपकी पार्टी का नाम नहीं आता। I can assure you, because it is

not done party-wise. There were seven names which were given to the Secretariat, and I would have called the seven names and closed the list. Some of the Congress Members have withdrawn their names. I am trying to accommodate everybody.

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra): Madam, I have given my name early in the morning.

उपसभापति : हां, आपका था, इनका नहीं था। इनकी बात हो रही है। देखिए, मनमोहन सिंह जी का, नरेन्द्र मोहन जी, सलीम, सतीश प्रधान, ब्रतीन सेनगुप्त, गुलाम नबी आजाद और एक और कांग्रेस के संतोष बागड़ोदिया थे, उन्होंने विदड्रॉ किया, ब्रतीन ने विदड्रॉ किया, इसलिए कि सब एकोमोडेट हो जाएं, सब लोग बोल सकें। सबकी भावनाएं एक हैं। हम कोई नई बात इसमें नहीं कह सकते इसके अलावा कि यह बहुत ही दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए थी।

श्री संजय निरुपम : इतने समय में तो मैं अपनी बात रख देता।

उपसभापति : पर अभी होम मिनिस्टर साहब को बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, this is most unfair. We want to hear the Home Minister.

श्री संजय निरुपम : मैडम, मैंने लंच ऑवर में ...**(व्यवधान)**... पहले बात की है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : आप होम मिनिस्टर साहब को बता दीजिएगा। आप उनको बोलने दीजिए। बोलिए।

श्री संजय निरुपम : नहीं, मैडम, मैं ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: After the ruling, it is over.

श्री संजय निरुपम : मैं तो सरकार की कोई आलोचना करने नहीं जा रहा हूं। लेकिन वहां अभी भी कुछ लूपहोल्ज ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is not a question of *alochana*.

श्री संजय निरुपम : उन्हें मैं यहां क्यों नहीं रखूं?

उपसभापति : बोलिए, होम मिनिस्टर साहब, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): आपकी बात तो एनडीए में भी हो सकती है। ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sanjay Nirupam, you cannot pressurise people. You cannot pressurise the House. होम मिनिस्टर साहब, आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)... आप ऐसा नहीं करिए। आप हर बार झगड़ा मत किया कीजिए।

SHRI S. VIDHUTHALAI VIRUMBI: The Chair has already given the ruling.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Everbody wants to the hear the Home Minister. बोलिए।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदया, संजय निरुपम जी की वेदना मैं समझ सकता हूं और इतने बड़े हत्याकांडों के बाद आज के दिन अगर कोई आलोचना करे तो मैं उनको दोष नहीं दूंगा।

श्री संजय निरुपम : मैं कोई आलोचना करना नहीं चाहता। ...(**व्यवधान**)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, कोई करना भी चाहे, लेकिन ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम : मैं कोई इन्फोर्मेशन देना चाहता हूं, जो आपके पास नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : आप जरूर दे दीजिएगा। होम मिनिस्टर साहब इसी पार्लियामेंट में हैं। होम मिनिस्टर हैं, आज हैं और कल भी रहेंगे। आप जरूर दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम : जम्मू के कैंप में जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं वे शायद नहीं बचेंगे, क्योंकि वहां पर सैक्युरिटी अरेंजमेंट्स नहीं हैं। सिर्फ एक सिपाही वहां पर खड़ा है। मैं नाम बता देना चाहता हूं। मिस्री वाला कैंप है। उस कैंप में इस समय एक भी सिपाही नहीं खड़ा है। वे सारे सॉफ्ट टॉर्गेट हैं। आतंकवादियों के वे सॉफ्ट टॉर्गेट हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : बैठिए। देखिए, हर मामले में ...(**व्यवधान**)... संजय जी ...(**व्यवधान**)...

श्री संजय निरुपम : मैं तो बैठ जाऊंगा ...(**व्यवधान**)... लेकिन वे कश्मीरी पंडित नहीं बचेंगे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI P.N. SIVA (Tamil Nadu): Madam, this is too much.

SHRI S. VIDHUTHALAI VIRUMBI: When the Leader of the House and the Leader of the Opposition speak, high priority should be given to them. That custom should not be disturbed. We give priority to the observations made by the Leaders of the House and the Leader of the Opposition.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपने जो अभी जानकारी दी है और भी कोई देंगे तो मैं ...(**व्यवधान**)...और आवश्यक सूचना वहां अभी भेज दूंगा। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति : बोलिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदया, कुछ बातों पर हरेक सदस्य जो बोला वह एक ही बात बोला कि इस प्रकार के काण्डों की सूचना पाकर सभी को धक्का लगा है और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन के परिवारों के प्रति सब ने संवेदना प्रकट की है। उस पर भी हम सब सहमत हैं। जिन लोगों ने यह कुकृत्य किये हैं वे किसी देश की, किसी धर्म की, किसी की भी सेवा नहीं कर रहे हैं। वे इंसानियत के दुश्मन हैं। वह केवल भारत के दुश्मन नहीं हैं, वह इंसानियत के दुश्मन हैं' यह बात भी सभी ने प्रायःअपने ढंग से बार-बार कही है, माननीय विपक्ष के नेता ने उस को सवाल के रूप में मेरे सामने रखा कि आप को क्या लगता है, इस के पीछे मोटीवेशन क्या है? महोदया, मैं ने अपने वक्तव्य में खुद कहा है कि मैं मानता हूं कि इमीडिएट जो मोटीवेशन है या प्रोवोकेशन है, यह हिजबुल मुजाहिदीन की पहल है। साधारणतः आतंकवादी आतंक के द्वारा, हत्या के द्वारा आतंक पैदा करना चाहते हैं, पर इस बार मुझे लगता है कि शायद लश्करे तोयबा स्वयं आतंकित है कि कहीं शांति न हो जाय, चाहे वह बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है।

महोदया, यहां पर सलीम साहब ने या किसी ने जिक्र किया था कि एक बार त्रिसूत्री बात कही थी, थ्री-प्रोंग्ड बात कही थी और तब मैं ने जानबूझकर कहा था और उस का जम्मू-कश्मीर से ही सम्बंध नहीं था। मैं ने कहा था कि हम आतंक जहां पर भी है, वहां पर चाहेंगे कि सरकार का दृष्टिकोण तीन दिशाओं में चले। एक तरफ तो जो हिंसा करते हैं, उन के साथ कठोरता से व्यवहार किया जाए, कठोरता से उन का नियमन किया जाए और जहां तक संभव हो, उन को बिल्कुल क्रश किया जाए। लेकिन दूसरी बात मैं ने यह कही थी कि बहुत सारे लोग कई कारणों से गलत रास्ते पर चले गए हैं वे अगर अपनी समस्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं तो उन के साथ बात करने की तत्परता सरकार की रहेगी। तीसरी बात, हम ने यह भी कही थी कि यह सब करते हुए भी अगर साधारण जनता का आर्थिक मामलों में, क्षेत्रों में विकास नहीं होगा, उन को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर वह पहली दो बातें किसी काम की नहीं होंगी। मैंने जब तीन सूत्रों की बात कही तो इन तीन सूत्रों की बात कही थी और उदाहरण दिया था कि यही रवैया नागालैंड में अपनाया गया, जहां नागा विद्रोही हैं, यही रवैया बोडो क्षेत्र में अपनाया गया जहां बातचीत शुरू हुई है, उन्होंने रिस्पांड किया है। मैं आशा करता हूं कि कश्मीर में भी, आसाम में भी लोग रिस्पांड करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता था कि It is merely a wishful thinking. यह किसी ने जब यहां पर आज कहा तो मुझे आश्चर्य हुआ! कम-से-कम जब यह हाइजैकिंग का काण्ड हुआ था तब किसी के मन में यह कल्पना नहीं थी कि उन को छोड़ देने से वह बातचीत करेंगे। उन को छोड़ देने के बाद उन्होंने दुनिया भर की और तीखी बातें की। लेकिन हां, पिछले दिनों कई फैक्टर्स के कारण लगता है कि जो तीन-चार प्रमुख तंजीम हैं जम्मू-कश्मीर में, जिन में से एक हिजबुल मुजाहिदीन भी प्रमुख तंजीम है, एक लश्करे तैबा है, तीसरी हरकत-उल-अन्सार है और इन में से स्वराज जी ने सही कहा कि हमारा अंदाजा है कि हिजबुल मुजाहिदीन एकमात्र वह तंजीम है जिस में अधिकांश कश्मीर के ही लोग हैं जब कि बाकी जितनी तंजीम है, प्रायः उन में अधिकांश लोग बाहर के हैं, विदेशी लोग हैं, कश्मीर के लोग कम हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कम हैं। इसीलिए जब हिजबुल मुजाहिदीन ने यह पहल की, इस का अंदाजा थोड़े दिन पहले उन की औपचारिक घोषणा से भी हुआ था कि यह हो सकता है संभावना है और इसी स्टेज पर जब हम को अंदाजा लगा तो हम ने जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री से भी बातचीत कर के उन को इस बात से अवगत कराया कि इस बात की संभावना है, आप को क्या लगता है? उन्होंने कहा कि इस से अधिक खुशी की बात क्या हो सकती है कि अगर कोई तंजीम जो पहचानी हुई है, जो हिंसा करती रही है और जो न केवल हिंसा करती रही है लेकिन जिन को क्योंकि जमीन

का पता है, वहां के क्षेत्र का पता है तो इस कारण वह जो बाकी की तंजीमें हैं, उन की सहायता भी बहुत कर पाती हैं, उनके बिना उन के लिए कुछ कठिन होगा।

जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री को, वहां के राज्यपाल को अवगत करवाकर और उस आधार पर कि वे भी इस बात के लिए तैयार रहें कि ऐसी संभावनाएं हैं और जैसे ही उनकी औपचारिक घोषणा हुई, तो सब लोगों से सलाह-मश्विरे के बाद सिक्युरिटी फोर्सिस से कहा गया कि यह घोषणा हुई है लेकिन इस घोषणा के कारण हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई हिंसा करना चाहता है तो उसके साथ कठोर व्यवहार, जैसा हम पहले करते थे, करना चाहिए।

गुलाम नबी आज़ाद ने एक बात कही कि टेलीविज़न पर रोज़ घोषणा हो रही थी, लगातार घोषणा हो रही थी, मैं नहीं जानता हू कि क्या घोषणा हुई, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कहीं नागा क्षेत्र मे भी सीज़-फायर हुआ तो सीज-फायर होने के बाद ये भी स्वाभाविक रूप से अपेक्षा करते हैं कि हमारी ओर से भी कम से कम उनकी बात को माना जाएगा। तो यह कहा गया कि ठीक है, यह हिजबुल मुजाहिदीन का है, लश्करे-तोएबा का नहीं है, हरकत-उल-अंसार का नही है। फिर ये सवाल उठे, जो आज आपने उठाए हैं और उनपर चर्चा होकर उन पर कुछ निर्णय हुए कि भाई, पहचानेंगे कैसे, कैसे पता लगेगा, कहां पता लगेगा। ये सारी चीज़ें डिटेल्स में वर्क-आउट की जाती हैं, वहां पर भी की जाती हैं जहां एन.एस.सी.एम. (आई-एम) है, एन.एस.सी.एम. (के) नहीं है, एक के साथ समझौता है। तो जो एक अनुभव पिछले दिनों में इस प्रकार की घोषणा के बाद हुआ कि किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए और किस प्रकार का काम करना चाहिए, इसका थोड़ा-बहुत अनुभव सुरक्षाकर्मियों को है और उसके आधार पर वे चल रहे थे। अभी तक कुछ हुआ नहीं, जिसके आधार पर कह सकें कि बातचीत शुरू हो गई - यह हुआ, वह हुआ, नहीं हुआ। अभी बातचीत शुरू नहीं हुई। उसके बारे में भी सावधानी थी कि बातचीत करे तो कौन करे, किसके साथ करे, क्या करे। ये सवाल हैं। आपने जो सवाल पूछा मोटिवेशन का, मैं समझता हूं कि मोटिवेशन साफ है। मोटिवेशन यह है कि इतने सालों से जिस जम्मू-कश्मीर को हमने हिंसा और हत्या का एक अड्डा बना रखा है, वहां पर शांति नहीं आनी चाहिए। वहां शांति किसी सूरत में नही आनी चाहिए, यह मोटिवेशन है। यह ठीक है कि प्रॉक्सी वार करने वाले पूरी तरह से मन मे यह भी मोटिवेशन रखते हैं कि जम्मू-कश्मीर राज्य की जैसी रचना है, उसमें यदि साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो जाए, साम्प्रदायिक हिंसा हो जाए और धीरे-धीरे उस साम्प्रदायिक हिंसा का असर बाकी देश में भी हो जाए तो हम अपने सामने जो उद्देश्य रखते हैं और उस उद्देश्य के बारे में हमको समझना चाहिए कि हमारा पड़ोसी देश, जिसने यह प्रॉक्सी वार चला रखी है, उसका लक्ष्य केवल मात्र जम्मू-कश्मीर की धरती पर कब्ज़ा करना नहीं है, उसका लक्ष्य है भारत को अस्थिर करना, भारत को अनस्टेबल करना। उनके यहां तो लम्बे-लम्बे लेख लिखे जाते हैं कि किस प्रकार से भारत का विघटन संभव है, अगर हमने ठीक प्रकार से काम किया तो। इन उद्देश्यों को समझकर हम अपनी प्रतिक्रिया बनाते है और प्रतिक्रिया बनाते हुए हमने यह तय किया कि हम कॉशियसली लेकिन रिस्पांड करेंगे, पॉज़िटिव रिस्पांड करेंगे।

आपने पाकिस्तान सरकार के बारे मे पूछा है, मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता। इतना कह सकता हूं कि हमें जितनी जानकारी मिली है उससे लगता है कि काफी कन्फ्यूजन है वहां पर कि क्या किया जाए और पिछले कुछ ही दिनों के घटनाक्रम की जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से लगता है कि वे चाहते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन को बिल्कुल आइसोलेट किया जाए,

हिजबुल मुजाहिदीन सफल न हो। अब निश्चित रूप से तो कुछ कहना मुश्किल है लेकिन अंदाज़े जो लग सकते हैं, उनका मैंने ज़िक्र किया इस सदन के सदस्यों के सामने। इसका मतलब यह है कि हमको इस बात से सावधान रहना चाहिए, हमारे पड़ोसी देश के क्या इरादे हैं, उस बारे में भी सावधान रहना चाहिए। Is it exercising the restraining influence? यह पूछा गया है। इस बारे में इतना ही कह सकता हूं कि पाकिस्तान के पास तो यह अर्थ है कि यह जो 80 लोग मारे गए हैं, जिनके बारे में मैंने विवरण दिया है, अभी-अभी मेरे पास एक स्टेटमैंट आया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें भारत की सिक्युरिटी फोर्सिस ने मारा है। अब यह है उनका रेस्ट्रेनिंग इन्फ्ल्युएंस। एक बात पर सभी लोग सहमत थे और किसी ने यह नहीं कहा कि इस घटनाक्रम के कारण या इस हत्याकांड के कारण हिजबुल मुजाहिदीन ने जो पहल की है, उसका रिस्पांस पॉज़िटिव नहीं होना चाहिए। इक्का-दुक्का ने आशंका प्रकट की कि कहीं वे हमको धोखा तो नहीं दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से एक आदमी सीज़फायर की बात करे और दूसरा हिंसा और हत्याकांड चलाता रहे? मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से जो लोग इन बातों को डील करते हैं, उनकी समझदारी और उनकी योग्यता पर देश को भरोसा रखना चाहिए और संसद को भी भरोसा रखना चाहिए। एक-एक कदम जो वे उठाएंगे, फूंक-फूंककर उठाएंगे, सावधानी से उठाएंगे, कोई गलती नहीं होगी।

महोदया, अनेक लोगों ने यह सवाल पूछा है और यह सवाल मेरे मन में भी उठा कि क्या वहां सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऐडिक्वेट थे? जैसे होने चाहिए थे, वैसे थे? अगर ऐडिक्वेसी का मतलब यह है कि कुल मिलाकर फोर्सेज कितनी लगीं तो मेरे पास जो लंबी-चौड़ी लिस्ट है, उसे देखकर मैं कह सकता हूं कि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेज एक यात्रा के लिए लगीं तो इन्हें ऐडिक्वेट तो मानना ही चाहिए। हां, इतना जरूर है कि आर्मी की ड्यूटी तो ज्यादातर area domination all along the yatra थी। So far as Army deployment is concerned, it is five battalions for the Yatra. It is not a small number.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : इसके बाद भी वे मारने में कामयाब हो गए?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, यह तो हुआ। यह एक स्थान पर हुआ जहां पर आर्मी नहीं थी। उस स्थान पर सी.आर.पी.एफ. थी, लोकल पुलिस थी, जहां पर यह घटना हुई है।

Therefore, as you have put this question, I had also put this question. I asked, "क्या हुआ, कितने लोग थे, कैसे थे, किस समय आए, आप लोग कब पहुंचे "? लगता यह है कि जब लोग पहले पहुंचे, तब वहां पर सी.आर.पी.एफ. नहीं थी और वे बाद में पहुंचे और उनको ऐलिमिनेट किया है। यह हुआ है लेकिन मैं इन बातों को ध्यान में रखता हूं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कोई कमी रही है। इसीलिए जब मैं सरकार की ओर से ऑफिशियली कहता हूं कि यात्रा चलनी चाहिए और यात्रियों को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए तो उसके लिए जहां-जहां पर भी लूपहोल्स रहे हैं, उनको प्लक करना चाहिए। यह मेरी रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है और सुरक्षाकर्मियों की रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है।

दूसरी चीज जिसे मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि एक ओपनिंग अगर हिजबुल मुजाहिदीन ने की है तो हिजबुल मुजाहिदीन जब तक उस पर दृढ़ है, तब तक भारत सरकार की ओर से उस पर पॉज़िटिव रिस्पांस ही होगा। मैं जानता हूं कि कुछ लोग जो हिजबुल मुजाहिदीन में दूसरे से प्रभावित हो सकते हैं, वे उस तरफ हैं। जो इस तरफ हैं वे तो शायद ठीक प्रकार से

करेंगे और इस दिशा में अगर प्रयत्न चलेगा तो वर्षों से जम्मू-कश्मीर में जिस शांति की अपेक्षा हम लोग करते रहे हैं, जिसका जिक्र अभी शायद गुलाम नबी आज़ाद ने किया कि जिस दिन यह घोषणा हुई हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से, बहुत क्षेत्रों में बहुत खुशी का इजहार हुआ। खुशी का इजहार होना स्वाभाविक है। महोदया, कश्मीर की प्रॉब्लम का कोई सौल्यूशन निकले, इसके लिए तो बहुत लोगों से वार्ता करनी पड़ेगी। सही कहा किसी ने कि केवल मिलिटेंट आऊटफिट से बात नहीं करनी होगी, जो पोलिटिकल फोर्सेज में हैं और जो कमिटेड हैं भारत की एकता और अखंडता के प्रति इतने वर्षों से, उनसे बातचीत करनी होगी कोई सौल्यूशन अगर हमें निकालना है तो। लेकिन इस समय जो फर्स्ट फेज़ था, वह फर्स्ट फेज़ इससे निकला जब हिजबुल मुजाहिदीन ने कहा कि आज तक हम मिलिटेंसी के रास्ते पर थे, हम इससे हटकर, बंदूक छोड़कर बातचीत करने के लिए तैयार है। तो फर्स्ट फेज होता है कि वहां पर शांति स्थापित कैसे हो, इसकी दृष्टि से क्या इलाज किया जाए?

महोदया, और भी कई बातें कही गई हैं कि शांति स्थापित हो और बातचीत शुरू हो, फिर भी उस शांति को भंग करने के लिए ये लश्करे-तोयबा आदि प्रयास करना चाहेंगे। इसके बारे में हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, जितनी अब तक बरती थी, उससे भी ज्यादा बरतनी पड़ेगी, मैं इससे इंकार नहीं कर सकता। एक दिन जब मैं दूसरे सदन में बोल रहा था तो किसी ने कहा कि लश्करे-तोयबा ने माना है कि हमने यह किया है। मुझे नहीं पता, मैं जानता नहीं हूं लेकिन अंदाज़ा हमारा यही है कि यह काम प्रमुख रूप से लश्करे-तोयबा का है। प्रमुख रूप से और जो दो लोग - मिलिटेंट मारे गए हैं वह भी लगता है कि उन्हीं के अंग हैं, उन्हीं के कैडर्स हैं। जब पूरी जांच होगी तो पता लग जाएगा। धन्यवाद।

उपसभापति : अब इतने सवालात होने के बाद कुछ नहीं लगता। होम मिनिस्टर साहब, एक सवाल किसी ने पूछा कि हजारों लोग इस आतंकवाद के कुर्बान हैं। कितने ही लोग मारे गए हैं -तीस हजार, 35 हजार, कितने हैं, तो उन लोगों का आप ब्रेकअप दे दें That can expose Pakistan's hand in it when they take the name of Islam; for them *atankvaad* is the religion, not any other thing.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वैसे इसके बारे में कुछ प्रश्न हुए हैं जिन प्रश्नों के उत्तर में हमने ब्रेकअप भी दिया है कि कितने-कितने आतंकवादी मारे गए हैं, कितने हमारे सैनिक मारे गए हैं - सुरक्षा कर्मी मारे गए, कितने सिविलियन मारे गए हैं, वह सब दिया है। अगर सदन चाहेगा तो एक बार मैं फिर से दे सकता हूं।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : वे हथियार कैसे आते हैं और हत्यारे हिन्दुस्तान में कैसे आते हैं, जरा उसको तो बताइए?

उपसभापति : सब को मालूम है कि ...(व्यवधान)...

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : वे हथियार कैसे आते है और वे हत्यारे कैसे आते हैं और अगर उन हथियारों को रोक दिया जाए, उन हत्यारों को रोक दिया जाए तो पूरा सोल्यूशन निकलेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हथियार पूरब से ही आते हैं और कई रास्तों से आते हैं केवल पश्चिम की ओर से नहीं आते।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : क्या पश्चिम की तरफ से भी आते हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आते हैं, मैं तो कहता हूं कि जो पश्चिम से भेजते हैं वे ही प्रमुख रूप से भेजते हैं, वे कभी-कभी पूरब से भी भेजते हैं, उत्तर पूरब से भी भेजते हैं।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : उनको रोकने के लिए हमारे यहां क्या किया जा रहा है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उसके लिए पड़ौस के देशों से भी बातचीत होती है। हमारी बोर्डर मेनेजमेंट की व्यवस्था अच्छी हो उसका प्रबंध किया जा रहा है और आपकी जानकारी के लिए मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जो संकट पैदा हो गये हैं इस प्रोक्सी वार से, उस पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आने वाली 5 तारीख को आमंत्रित किया गया है जिसको स्वयं प्रधान मंत्री सम्बोधित करेंगे।

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: What about the identity of the persons who have been killed so that their relatives... *(Interruptions)*

उपसभापति : वह नाम आप ऐलान कर दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, मैं अभी बतलाता हूं। अभी-अभी मुझे जानकारी मिली है कि जम्मू व कश्मीर की सरकार ने 8 मृत शरीर जेट और इंडियन एयर लाईंस से दिल्ली भेजे हैं। जिन लोगों को आइडेंटिफाइड किया गया है उन 11 लोगों की सूची मेरे पास है। इन 11 लोगों में से सूरज सिंह और इरशाद अहमद हैं। यह दोनों पुलिस कांस्टेबिल थे। लेकिन बाकी लोगों में ब्रहमकांता दिल्ली की है और रतन लाल चित्तोड़ गढ़-राजस्थान के हैं। विश्व नाथ दास पटना-बिहार के हैं। रमेश प्रसाद जयप्रकाश नगर, उत्तर प्रदेश के हैं। ऋतुराज वर्मा नौतनवा महाराजगंज उत्तर प्रदेश के हैं। मुस्ताक अहमद स्थानीय हैं जो अनंतनाग के हैं, जो इसमें मारे गए हैं। नरेश गोयल मेरठ के हैं तथा निशा गोयल इनकी पुत्री हैं और गितु गोयल इनका पुत्र है।

अभी तक जो आइडेंटिफाइड नाम जम्मू व कश्मीर की सरकार ने भेजे हैं उसके साथ उन्होंने यह भी सूचित किया है कि जितनी जानकारी मिलती जाएगी वह यहां पर जम्मू कश्मीर हाऊस के रेजीडेंट्स कमिश्नर को देते रहेंगे।

उपसभापति : होम मिनिस्टर साहब, अगर यह टेलीविजन पर भी दे दें तो भारत के अलग-अलग इलाकों से हजारों-लाखों लोग जा रहे हैं तो उनके परिवार के लोगों को चिंता नहीं रहेगी। टी.वी. पर भी यह इत्तला आनी चाहिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): यहां घरों से निकाल कर 20 मजदूरों को मारा गया है जो प्रवासी मजदूर थे। क्या उनकी पहचान नहीं हुई है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरे पास केवल उनके बारे में सूचना आई है जो पहलगाम की घटना के यात्री थे।

श्री सतीश प्रधान मैडम्....

उपसभापति : अभी हाउस एडजोर्न करने दीजिए।

श्री सतीश प्रधान : अभी संजय निरुपम जी ने जो बात कही थी कि जम्मू मे जो पंडित रहते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जाए।

उपसभापति : होम मिनिस्टर साहब, संजय निरुपम जी ने जो बात कही है -जम्मू में जो कश्मीरी पंडित लोग हैं उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम बराबर आप कर लीजिए।

The House is adjourned till 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-five minutes past seven of the clock, till eleven of the clock on Thursday, the 3rd August, 2000.

MGIPRRND—122 RSS/2001—300 Copies